www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 36 | गोरखपुर, 23 मार्च 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

▸ कोऑपरेटिव बैंक की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक संपन्न

उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा रही है: योगी आदित्यनाथ

ग्राहकों को बैंकों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्मार्ट बैंकिंग गाइड पुस्तक का विमोचन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 'उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक' की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक में कहा कि सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा रही है। उन्होंने इस अवसर पर 'उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक' के जिला सहकारी बैंकों और अन्य शेयर धारकों के खातों में 75 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश की धनराशि ऑनलाइन भेजी।

योगी आदित्यनाथ ने ग्राहकों को बैंकों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्मार्ट बैंकिंग गाइड पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को ऋण के प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश के 16 जिला सहकारी बैंक बंद हो गए थे, उनके लाइसेंस जब्त कर लिए गए थे लेकिन प्रदेश सरकार के समक्ष उन्हें संचालित करने की चुनौती थी। उन्होंने कहा हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकारिता आन्दोलन को एक नई जान दी और आज सहकारिता ने एक नया स्वरूप लेना प्रारम्भ किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में सबसे ज्यादा सम्भावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक लाभांश अर्जित करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बैंकों के साथ बेहतर तालमेल बनाया है और इस बेहतरीन तालमेल के कारण आज यह चीजें वहां तक पहुंची हैं।

सीरिया को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता

सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा सीरियाई तट के गांवों और इलाके के लोगों की हत्या, कब्जा और यातना के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरी चिंता जताई जा रही है। सीरिया की अंतरिम सरकार ने देश के तटीय इलाकों लताकिया और टार्टस में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। लताकिया में अलावाइट्स, सुन्नी मुस्लिम और ईसाई जैसे जातीय और धार्मिक समूह रहते हैं। लाताकिया सीरिया का अलावाइट बहुल क्षेत्र है, और यहां अलावाइट समुदाय का विशेष प्रभाव है। टार्टस सीरिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, और यहां अलावाइट समुदाय की अधिकता है। यह इलाका बशर अल-असद का प्रमुख गढ़ माना जाता है। देश के तटीय इलाकों में अलावी और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय पर सुरक्षा बलों के हमलों का असर देश के दूसरे कई इलाकों पर पड़ रहा है, और इससे तनाव गहरा गया है।

मोहम्मद अल-जुलानी देश में बाहरी हस्तक्षेप रोकने की बात कह रहे थे लेकिन उनके कदम ठीक इससे उलट दिखाई दे रहे हैं। सीरिया की सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेशेवर सेना तैयार करने के लिए देश के सशस्त्र बलों में उइगर, जॉर्डनियन और तुर्क सहित कुछ विदेशी लड़ाकों को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उनका यह कदम अन्य जातीय-धार्मिक समूहों के लिए विचलित करने वाला है। जुलानी का आईएस से गहरा संबंध रहा है, और दुनिया के इस सबसे दुर्दात आतंकी संगठन का किसी देश में सीमा पर कोई विश्वास नहीं है, आईएस को विदेशी लड़ाकों की सुस्थापित सैन्य इकाई माना जाता है। जुलानी ने आईएस से अलग होकर ही हयात तहरीर अल-शाम नामक गुट बनाया था और वे खुद को उदार नेता के रूप में प्रस्तुत कर सीरिया के कई जातीय समूहों का विश्वास जीतने में सफल भी हो सके। लेकिन अब जब देश की कमान उनके हाथ में आई तो उन्हें लेकर आशंकाएं भी कम नहीं हैं।

एचटीएस की स्थापना 2011 में एक अलग नाम, जबात अल-नुसरा के तहत अल-कायदा के प्रत्यक्ष सहयोगी के रूप में की गई थी। स्वयंभू इस्लामिक स्टेट का नेता अबू बक्र अल-बगदादी भी इसके गठन में शामिल था। अल-जुलानी ने सार्वजनिक रूप से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से नाता तोड़ लिया है, लेकिन वे सुन्नी मुसलमान हैं, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं।

खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहते हैं, जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। यह इस्लाम की पारंपरिक और प्राचीन विचारधारा है, जिस पर बहुसंख्यक सुन्नी भरोसा करते हैं। दुनिया में आईएस के उभार के केंद्र में इस विचारधारा को रखा गया जब एक दशक पहले इस्लामी चरमपंथी संगठन आईएस ने इराक और सीरिया में अपने कब्जे वाले इलाकों में खिलाफत यानी इस्लामी राज्य का ऐलान किया। शिया मुसलमान इतिहास की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते।

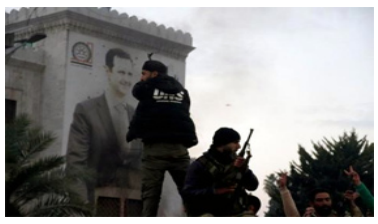

राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक हिंसा, चरमपंथ, आतंकवाद और विदेशी हस्तक्षेप सीरिया की प्रमुख समस्या रही हैं, और लगता है कि असद के पतन के बाद भी मध्य-पूर्व के इस देश में शांति लौटती हुई दिखाई नहीं दे रही है।

असद के समर्थकों को मोहम्मद अल-जुलानी पर भरोसा नहीं है, और उनकी आशंका सच भी साबित हुई है। अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के हजारों लोगों को मार दिया गया है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि हयात तहरीर अल-शाम के सुरक्षा बलों को पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थकों से लड़ने के लिए भेजा गया है।

असद के जाने के बाद शिया गहरे दबाव में हैं। अलावी, इस्माइलिस और अन्य शिया सीरिया की आबादी का करीब तेरह फीसद हिस्सा हैं। बशर अल-असद सरकार के पतन से पहले उनकी शासन व्यवस्था में सकारात्मक स्थिति मौजूद थी। हयात अल-शाम को सुन्नियों का संगठन माना जाता है, यदि इस विद्रोही संगठन ने शियाओं को निशाना बनाने की कोशिश की तो सीरिया में ईरान और तुर्की के हित भी टकराएंगे। सीरिया में तुर्की ईरान की जगह ले सकता है।

सीरिया की बाईस मिलियन आबादी में से दसवां हिस्सा ईसाइयों का है। रूस खुद को बीजान्टिन साम्राज्य और उसकी रूढ़िवादी ईसाई धार्मिक विरासत के प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखता है, जो सीरियाई रूढ़िवादी ईसाई चर्च से बहुत जुड़ा हुआ है। वहीं अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी रूस सीरिया में बने रहना चाहता है, जिससे वह पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक अपनी मौजूदगी को बढ़ा सके। भूमध्य सागर में रूस की रणनीति तीन प्रमुख लक्ष्यों पर केंद्रित है, भूमध्य सागर की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठा कर अपनी सुरक्षा में सुधार करना, भूमध्य सागर में अपनी स्थिति का उपयोग करके अमेरिका के लिए एक वैकल्पिक विश्व शक्ति के रूप में रूस की स्थिति को बढ़ाना और सीरिया में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना। रूस का काला सागर बेड़े के लिए एकमात्र भूमध्यसागरीय नौसैनिक अड्डा सीरिया के बंदरगाह शहर टार्टस में स्थित है। टार्टस सीरिया के पश्चिमी तट पर स्थित है, और यहां अलावाइट समुदाय की अधिकता है। अब अलावी समुदाय के लोग रूस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। सीरिया में रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका का गहरा दखल है। तुर्की सीरिया की वर्तमान सुन्नी सरकार को समर्थन देकर कुदरे पर दबाव बढ़ा रहा है।

सीरिया में तुर्की की प्राथमिक रुचि उत्तरी सीरिया में कुर्द समूहों से लड़ने के लिए एक बफर जोन और एक पुलहेड बनाने की रही है। उत्तरी सीरिया के कुर्द बल में कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स मिलीशिया का दबदबा है। तुर्की इसे अपनी सीमा पर मौजूद खतरे की तरह देखता है। तुर्की कुदरे के एक हिस्से को आतंकवादी समूह बताता है। असद को ईरान का समर्थन हासिल था लेकिन अब तुर्की समर्थक सरकार बनने से मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। मोहम्मद अल-जुलानी को अपने देश में शांति की स्थापना के लिए विदेशी हस्तक्षेप को रोकना होगा और सभी वगरे से बातचीत कर सर्वमान्य सरकार बनाना होगा। फिलहाल, जुलानी आर्दोआन के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं, और यह स्थिति सीरिया में गृह युद्ध की आशंका को बढ़ा रही है।

सांस्कृतिक मर्यादा में रहना चाहिए राजनति को

राजनीति को सांस्कृतिक मयार्दा में रहना चाहिए। मर्यादित राजनीति समाज को उत्कृष्ट बनाने में भी उपयोगी रहती है। संस्कृति विहीन अमर्यादित राजनीति तनाव पैदा करती है। भाषा सामाजिक एकता और सुख-दुख बांटने का उपकरण है। राष्ट्रजीवन के सभी व्यापारों के संचालन में भाषा की ही भूमिका है। भाषा पर राजनीति से राष्ट्रीय क्षति होती है। इसलिए भाषा को बांटने वाली राजनीति का हथियार बनाया जाना उचित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तमिलनाडु में राष्ट्रभाषा हिन्दी के ही विरुद्ध टिप्पणियां की जा रही हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने धमकी भरे लहजे में कहा है, ₹हिन्दी हम पर न थोपी जाए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा।₹ स्टालिन ने इसी बात को बार-बार दोहराया है। वे मयार्दा तोड़ रहे है। रुपया भारतीय मुद्रा है। मुद्रा का भारतीय प्रतिरूप प्रतीक 'रु' तमिलनाडु में भी जारी था। लेकिन राज्य सरकार ने उसे भी हटा दिया है। उत्तर दक्षिण की बातें भी चल निकली हैं। केन्द्र की तरफ से बार-बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। लेकिन सतही राजनीति से वातावरण गरमा गया है । द्रविड़ और आर्य नस्ल की बातें भी चल निकली हैं। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से यह शुभ संकेत नहीं है। आर्य द्रविड़ नस्ल का सिद्धांत अनेक विद्वानों ने खारिज किया है। द्रविड़ और आर्य शब्द सामूहिक पहचान के संदर्भ में प्रयुक्त होते रहे हैं। कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार रहा है कि यह अलग-अलग रेस (नस्ल) हैं। एक विद्वान वीएस गुहा ने 'रेस एफिनिटीज ऑफ द पीपल ऑफ इण्डिया' नाम की पुस्तक लिखी थी । पुस्तक का विवेचन करते हुए सर आर्थर कीव ने लिखा था, ₹सीमा प्रांत के पठानों और त्रावणकोर की वन्य जातियों को मिलाने वाला सेतु मौजूद है।

तमिल के संगम साहित्य की रचना में भी बहुत ब्राह्मण विद्वानों ने सहयोग किया था। द्रविड़ संस्कृत का शब्द है। मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग द्रविड़ क्षेत्र के निवासियों के लिए किया है। कुमारिल भट्ट ने इसका प्रयोग भाषा की सूचना देने के लिए किया है । द्रविड़ों को अलग नस्ल या प्रजाति बनाने का काम यूरोपीय विद्वानों ने किया है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिनकर की लिखी 'संस्कृति के चार अध्याय' पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी। लिखते हैं, ₹सम्भावना यह है कि भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों और आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर, द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुए। इस मिलन, मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत करती है। संस्कृत और प्राचीन पहलवी, ये दोनों भाषाएं एक ही मां से मध्य एशिया में जन्मी थीं, किन्तु भारत में आकर संस्कृत ही यहां की राष्ट्रभाषा हो गई। यहां संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण, दोनों ने योगदान दिया। सच तो यह है कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिणवालों का अंशदान अत्यन्त प्रमुख रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी, वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। बुद्ध के समय से लेकर अब तक संस्कृत यहां की जनता की बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं रही है, फिर भी, सारे भारतवर्ष पर वह अपना प्रचुर प्रभाव डालती ही आई है।₹ नेहरू जी आर्यों को विदेशी मानते थे । सत्य यह है कि आर्य भारतीय ही थे। संस्कृति का विकास भारतवासियों ने किया । द्रविड़ सहित सभी जनों ने संस्कृति का संवर्द्धन किया है। उत्तर दक्षिण की बातें करना खतरनाक है। भारतीय समाज के किसी भी छोटे या बड़े समूह मध्य अलगाव सिद्ध करना सद्विचार नहीं है। भारत के सबसे बड़े दार्शनिक शंकराचार्य दक्षिण ही थे और रामानुज भी । चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु के ही थे । भारतीय दर्शन के व्याख्याता, दार्शनिक, राजनेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी तमिलनाडु के हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम भी दक्षिण के ही थे। ऐसे सभी विद्वानों ने समूचे देश में व दुनिया के अन्य देशों में भी भारतीय दर्शन और संस्कृति को प्रभावित किया है। देश के कोने-कोने सभी वर्गों समूहों में इन महानुभावों का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। भक्ति दर्शन का आदि क्षेत्र दक्षिण में ही था । हम सबको पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए।

विद्वान यह भी कहते रहे हैं कि भारत में दिखाई पड़ने वाली प्रजाति विविधताएं इस कारण हैं कि भारतीय जनता के सभी लोग भारत के बाहर से आए हैं। लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं की कि अनेक जातियों का विकास भारत में ही हुआ है।

आर्य भारत के ही मूल निवासी हैं। उन्हें विदेशी बताने का कार्य यूरोपीय साजिश थी। डॉ. आम्बेडकर ने आर्यों को भारत का मूल निवासी बताया है। उन्होंने लिखा है, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे।

डॉ. आम्बेडकर के अनुसार, आर्यों का मूल ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में नदियों और प्रतीकों के उल्लेख में भारत के ही स्थल हैं। आर्य किसी और देश के होते तो नदियों और स्थान के नाम भारतीय न होते। यूरोपीय विद्वानों के अनुसार आर्य मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में रहते थे। वह वहीं से भारत आए थे। यदि इस निष्कर्ष को सही मान लिया जाए तो प्रश्न उठता है कि आर्यों ने वेदों की तरह और कोई प्रामाणिक साहित्य अपने मूल देश लिए क्यों नहीं लिखा? कुछ विद्वानों ने द्रविड़ों को भी बाहर से आने वाला बताया है। आर्यों तरह द्रविड़ भी भारत के मूल निवासी हैं। सवाल यह भी उठाया जाता रहा है कि ऋग्वेद के रचनाकार आर्य भारत की नदियों को माता क्यों कहते हैं? किसी भी दूसरे देश से आया जनसमूह इस देश की नदियों को माता क्यों कहेगा? दर्शन, सभ्यता और संस्कृति पर वैदिक काल से लेकर पुराण काल तक विपुल साहित्य का सृजन हुआ है। इस पूरे साहित्य में कहीं आर्य आक्रमण के संकेत भी नहीं हैं। आर्यों के विदेशी होने का झूठ साम्राज्यवादी साजिश है। आर्यों और द्रविड़ों के बीच कोई तनाव नहीं रहा। लेकिन स्वार्थी राजनीति द्रविड़ आर्य संघर्ष बताती रही है। 1939 में एक विद्वान जूलियन हक्सले ने कहा था, प्रजातिवाद का सिद्धां झूठा है और खतरनाक भी है।

रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, आर्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले 1853 में मैक्समूलर ने किया था और 1939 में हिटलर ने प्रमाणित कर दिया कि आर्यों को प्रजाति मानने का सिद्धांत खतरनाक है। भारत को भी यह नहीं मानना चाहिए कि आर्य और द्रविड़ नाम की दो प्रजातियां हैं। मैक्समूलर ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की और कहा, ₹जब मैं 'एरियन' शब्द कहता हूं तब मेरा अभिप्राय न रक्त से होता है, न अस्थि, बाल और खप्पर से । मेरा तात्पर्य केवल उन लोगों से है जो आर्य भाषा बोलते हैं।₹ द्रविड़ शब्द प्रजातिवाचक नहीं है। सम्भवतः यह स्थान वाचक शब्द है । दिनकर ने याद दिलाया है कि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र में प्रधानता आर्य वंश की होनी चाहिए। लेकिन प्राचीन भारतीय यह नहीं मानते थे। द्रविड़ स्थान का विशेषण था। पंच द्रविड़ में पुराण काल में द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात इन पांच समूहों को गिनते थे। आर्यों और द्रविड़ों के बीच परस्पर प्रेम था। आर्यों की तरह द्रविड़ के ऋषि भी यज्ञ के पुरोहित होते थे। उन्होंने शास्त्रों की भी रचनाएं की थीं।

गोरैया जो कभी हर आंगन, छत तथा बगीचे में चहकती थी और हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज दुर्लभ होती जा रही है। प्यारा सा पक्षी, जो हमारे घरों और आसपास पेड़-पौधों पर बसेरा करता था, आज विलुप्ति के कगार पर है।

गोरैया के बिना आंगन सूना

एक समय था, जब सुबह आंख खुलते ही गोरैया की चहचहाहट से दिलोदिमाग को सुकून मिलता था लेकिन अब यह चहचहाहट कहीं गायब सी हो गई है। गोरैया का भारतीय लोक कथाओं और कविताओं में विशेष स्थान रहा है, और यह हमारी भावनाओं और जीवन के दैनिक अनुभवों का हिस्सा रही है। करीब दो दशक पहले तक यह चिड़िया हर कहीं झुंड में उड़ती देखी जाती थी लेकिन अब संकटग्रस्त पक्षी की श्रेणी में आ गई है। भारत के अलावा यूरोप के कई हिस्सों में भी गोरैया की संख्या काफी कम हो गई है। नीदरलैंड में तो गोरैया को ह्यदुर्लभ प्रजातिह्न की श्रेणी में ही रख दिया गया है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य जैसे देशों में भी इनकी संख्या तेजी से घट रही है। लोगों को गोरैया के संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 20 मार्च को ह्यविश्व गोरैया दिवसह्न मनाया जाता है। यह दिवस 2010 में ह्यनेचर फॉरएवर सोसायटीह्न द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद् मोहम्मद दिलावर ने की थी। गोरैया केवल पक्षी नहीं है, बल्कि हमारे बचपन की यादों, संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका जैव-विविधता में महत्त्वपूर्ण योगदान है। गोरैया छोटे कीटों और अनाज के दानों पर निर्भर रहती है, जिससे कृषि भूमि पर कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। गोरैया मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती है। यह खाद्य श्रृंखला का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और अन्य प्राणियों के लिए भोजन के स्रेत के रूप में भी कार्य करती है। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण गोरैया के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। पेड़ों की कटाई और पारंपरिक घरों की जगह कंक्रीट के भवनों ने इनके घोंसले बनाने की जगह सीमित कर दी है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण गोरैया की संख्या में भारी गिरावट आई है। मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन भी इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है। कृषि में कीटनाशकों, रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से गोरैया के लिए भोजन कम होता जा रहा है। पिछले दो-ढ़ाई दशकों में हमारी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया है। निहित स्वाथरे के चलते हमने जंगल उजाड़ दिए, प्रकृति का संतुलन चक्र बनाए रखने में सहायक जीव-जंतुओं और पक्षियों की अनेक प्रजातियों का शिकार करके या उनके आशियाने उजाड़ कर उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। इसका असर गोरैया पर भी पड़ा है। भोजन तथा पानी की कमी, पक्के मकान बनने से घोंसलों के लिए स्थानों की कमी, कटते पेड़-पौधे, हमारी बदलती जीवनशैली, मोबाइल रेडिएशन का दुष्प्रभाव, तापमान में बढ़ोतरी आदि प्रमुख कारण हैं, जो गोरैया की विलुप्ति के बड़े कारण बन रहे हैं। गोरैया की आबादी घटने का बड़ा कारण यह भी है कि कई बार उनके घोंसले सुरक्षित स्थानों पर नहीं होने के कारण कौए तथा दूसरे हमलावर पक्षी उनके अंडों तथा बच्चों को खा जाते हैं। आज की पीढ़ी प्रकृति और पक्षियों से दूर होती जा रही है। गोरैया संरक्षण के लिए जागरूकता की कमी भी इसके अस्तित्व के लिए चुनौती है। गोरैया के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिए। पारंपरिक घरों की संरचना को ध्यान में रखते हुए घोंसला बनाने के लिए स्थान प्रदान करने की भी आवश्यकता है। कृषि में जैविक तरीके अपना कर कीटनाशकों के उपयोग को कम किया जा सकता है, जिससे गोरैया के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ेगी। गोरैया को घोंसला बनाने में मदद के लिए लकड़ी या मिट्टी के छोटे घर बनाए जा सकते हैं। घर-आंगन या छतों पर अनाज और पानी रखने से गोरैया को भोजन प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। गोरैया संरक्षण के लिए स्कूल-कॉलेजों और सामाजिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की भी जरूरत है। हालांकि सरकार और वन्यजीव संरक्षण संगठनों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य गोरैया की संख्या बढ़ाना और इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना है। नेचर फॉरएवर सोसायटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी तथा अन्य संगठनों ने गोरैया संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। स्थानीय समुदायों और कुछ स्वयंसेवी संगठनों द्वारा घरों और सार्वजनिक स्थानों पर गोरैया के लिए घोंसले बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में तेजी लाने और इनका दायरा बढ़ाए जाने की जरूरत है क्योंकि यदि हम अभी प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में यह पक्षी केवल किताबों और कहानियों में ही बच पाएगा।

घूँघट की बगावत

23 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

2028 तक भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था : हरदीप

सोनभद्र। 22-03 केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2028 तक यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसमें ईंधन क्षेत्र का बड़ा योगदान होगा। वर्तमान में देश के राजस्व का 19 प्रतिशत ईंधन क्षेत्र से आ रहा है। ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता और इसे किफायती बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। भविष्य में इसमें और बदलाव दिखेंगे। शनिवार को सोनभद्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से कहा कि ईंधन की खपत बढ़ने के बाद भारत में पिछले तीन साल में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इसके पीछे पीएम मोदी का संकल्प कारण रहा। केंद्र सरकार ने दो बार पेट्रोल-डीजल पर सेस कम किया है। पीएम मोदी ने जब दायित्व संभाला था, तब बायो फ्यूल की ब्लेंडिंग 1.6 प्रतिशत थी, जो आज बढ़कर 20 प्रतिशत तक हो चुकी है। इसे और बढ़ाना है। एथेनाल, कंप्रेस बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सोनभद्र के विकास की भी प्रतिबद्धता जताई। इसके लिए जिले को एयर और रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने पर जोर दिया। यहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं को भी गति देने की बात कही।

केंद्रीय मंत्री ने जिले में पंचायती राज विभाग की ओर से शुरू किए प्लास्टिक मुक्ति अभियान की सराहना की। कहा कि पीएम मोदी ने लाल किले से देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने का आह्वान किया था। इस दिशा में सोनभद्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए इससे जुड़ी टीम बधाई की पात्र है। इस अभियान को मजबूती से जिले में आगे बढ़ाया जाएगा।

पांच करोड़ की 135 परियोजनाओं का किया शिलान्यास

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिले में विकास की 135 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब पांच करोड़ रुपये है। सांसद निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत परियोजनाओं में प्रमुख रूप से 151.23 लाख की लागत से 30 विद्युत हाईमास्ट लाइट का अधिष्ठापन, 83.88 लाख की लागत से 17 सार्वजनिक सोलर पेयजल संयंत्र, 16.03 लाख की लागत से 08 विद्युतीकरण, 80.72 लाख की लागत से 66 सोलर हाईमास्ट लाईट, 51.84 लाख की लागत से 06 पुलिया का निर्माण, 10 लाख की लागत से 01 सार्वजनिक सुलभ शौचालय, 6.70 लाख की लागत से 01 सोलर पावर प्लांट, 50 लाख की लागत से 03 विद्यालयों में भवन निर्माण और 18.54 लाख की लागत से 03 सार्वजनिक ओपेर जिम का निर्माण कार्य शामिल है।

महिलाओं को बांटे सोलर कूकर

लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकासखंड चोपन के ग्राम जुगैल के 300 ग्रामीणों को मुफ्त सौर उर्जा चूल्हा वितरित किया। उन्होंने महिलाओं से अब तक खाना बनाने वाले साधन की जानकारी ली। पूछा कि हम आएंगे तो इस पर क्या बनाकर खिलाएंगी। महिलाओं ने पूरे सत्कार की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक मेडिकल वैन भी प्रदान किया। इसकी चाभी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एसके सिंह को सौंपा। इससे पहले उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक ली।

जिले में चल रही विकास परियोजनाओं और जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोनभद्र को सोने की चिड़िया है। यहां के पर्यटन स्थल अद्भुत है।

इसके विकास के लिए काम शुरू हो गया है। अब इसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड, डीएम बद्रीनाथ सिंह, सीडीओ जागृति अवस्थी, एसपी-एसटी आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद आदि उपस्थित रहे।

एक रुपए में इलाज का दावा बेदम...बाहर की लिखी जा रहीं दवाएं

रामकोला। सीएचसी पर एक रुपए की पर्ची पर इलाज की उम्मीद मरीजों के अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दे रही है। सस्ता इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच रहे मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। मनचाही कंपनी की दवा लिखवाने के लिए सीएचसी में दवा एजेंट से लेकर दवा दुकानदारों का जमावड़ा और दबदबा है। अपनी बात को मनवाने के लिए वह विवाद से भी बाज नहीं आते। बुधवार को अस्पताल में हुए विवाद ने एक बार फिर सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

डॉक्टरों का तर्क है कि कुछ मरीजों ऐसे आते हैं, जिन्हें ऐसी दवाओं की जरूरत होती है जो अस्पताल में नहीं आती हैं। ऐसे में बाहर से कुछ दवाइयां लिखना मजबूरी हो जाती है। रामकोला सीएचसी पर बाहर से दवा लिखने और दवा दुकानदारों के हस्तक्षेप का खेल कोई नया नहीं है। इसके पहले भी दवा लिखने या अस्पतालों में दलालों के बीच विवाद हो चुका है और पुलिस तक मामला पहुंच चुका है। मामला बढ़ता है तो डॉक्टर कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत भी करते हैं, लेकिन बाद में मामला मैनेज हो जाता है और बाहरी दवा लिखने का खेल फिर शुरू हो जाता है। प्रतिदिन 400 ओपीडी के अलावा करीब दस प्रसव भी होता है।

गंगा शाखा की पत्रिका अविरल गंगा का हुआ लोकार्पण

वाराणसी। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा की ओर से वार्षिक पत्रिका अविरल गंगा का लोकार्पण महमूरगंज स्थित बालाजी पैलेस में हुआ। पत्रिका का लोकार्पण करते हुए समाजसेवी संजय लोहिया ने कहा कि समाज की महिलाएं आज राष्ट्रहित में आगे आ रही हैं। मनीषा अग्रवाल ने बताया कि समाज के हित में जो कार्य किए गए हैं, उसका पूरा विवरण इसमें दिया गया है। अध्यक्ष स्मिता लोहिया ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच गंगा शाखा 23 साल से लगातार महिलाओं के उत्थान व स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य कर रही है। संयोजन में कृष्णा चौधरी, उषा तुलस्यान, विनीता प्रसाद, उमा बजाज, निशा अग्रवाल, मधु तुलस्यान ने किया।

खुले आसमान तले खड़े होकर वाहनों का इंतजार करते है लोग

संतकबीरनगर। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर बने वाहन स्टैंडों पर न तो छाजन के इंतजाम किए गए हैं और न ही पीने के पानी की व्यवस्था ही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़नी तय है।

शहर में विभिन्न स्थानों को आने-जाने के लिए वाहन स्टैंड बनाए गए हैं। इनमें विधियानी मोड़, मेंहदावल बाईपास, बंजरिया, बैंक चौराहा के आगे सहित विभिन्न स्थान शामिल हैं। यहां पर न तो यात्रियों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है और न ही कहीं पर शेड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को धूप में खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्री खुले आसमान के तले खड़े होकर वाहनों का इंतजार करने को मजबूर हैं। अभी आगे गर्मी और बढ़ेगी तो यात्रियों की परेशानी में इजाफा होना तय माना जा रहा है, लेकिन अब तक जिम्मेदारों ने कोई इंतजाम करने की जहमत गवारा नहीं की है। यात्री अमित कुमार, राम अजोर आदि ने बताया कि वाहन स्टैंडों पर यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से वाहन स्टैंडों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

गिरता भूजल स्तर तरसते प्रयागवासी

प्रयागराज जिले का भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब, शहरवासी पानी के लिए तरसेंगे। आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल जिले में 0.45 सेंटीमीटर पानी का लेवल नीचे जा रहा है। सबसे खस्ताहाल नैनी और सिविल लाइंस क्षेत्र का है। यहां पर पानी 37.07 और 25.78 मीटर नीचे तक पहुंच चुका है। भूगर्भ विभाग के अनुसार, बारिश के बाद (2024) में शहरी क्षेत्र में नैनी, सिविल लाइंस के अलावा रानीपुर प्रयाग, सदर तहसील, न्यू कटरा, जार्ज टाउन, सर्किट हाउस, एडीए कॉलोनी नैनी, पीपल गांव, महेशपुर झूंसी में लगातार भूजल का स्तर घट रहा है। सबसे खराब स्थित नैनी की है, यहां पर बारिश के पहले भूजल स्तर 21.02 मीटर था, लेकिन बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है और भूजल स्तर 37.07 पहुंच गया।

सहसों और चाका ब्लॉक को क्रिटिकल जोन घोषित

भूजल और दोहन के स्तर पर सहसों और चाका ब्लॉक को क्रिटिकल जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा बहादुरपुर, रहीमापुर, मंदौर, प्रतापपुर, शृंग्वेरपुर, बहरिया, होलागढ़, सैदाबाद, मऊआइमा, फूलपुर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। भूगर्भ विभाग की हाइड्रोलॉजिस्ट अर्चना सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से गठित कमेटी भूगर्भ जल का आंकलन लगातार कर रही है। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी- चायल ब्लॉक, प्रतापगढ़- शिवगढ़, सदर, मानधाता और संडवा चंद्रिका इत्यादि को भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रदूषितजल का कारण गिरता जल स्तर

भूजल स्तर गिरने के कारण ही शहर में लगे ज्यादातर हैंडपंप दम तोड़ चुके हैं। कई घरों में लगे पंप भी जवाब दे चुके हैं। अब लोगों को सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ रहा है। यही नहीं गिरते जलस्तर के कारण पानी प्रदूषित भी हो रहा है। ऐसी जगहों पर भूजल की रिचार्जिंग की तुलना में इसका इस्तेमाल अधिक हो रहा है।

भूजल दोहन की ये पांच सबसे बड़ी वजह

बिना अनुमति के जगह-जगह कार वाशिंग सेंटर खुलना, हर दूसरे घर में सबमर्सिबल पंप का होना, रिचार्जिंग की तुलना में अधिक पानी का इस्तेमाल होना, भूजल दोहन करने वालों पर शिकंजा न कसना, बिल्डिंग व कार्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न होना

ऐसे तय किया जाता है मानक

सुरक्षित जोन- रिचार्जिंग की तुलना में 70 फीसदी तक भूजल का इस्तेमाल होना। सेमी क्रिटिकल- रिचार्जिंग की तुलना में 70 फीसदी से अधिक इस्तेमाल होना क्रिटिकल जोन-रिचार्जिंग की तुलना में 90 से 100 फीसदी तक इस्तेमाल होना। अतिदोहित- रिचार्जिंग की तुलना में 100 फीसदी तक इस्तेमाल होना

एरिया (भूजल स्तर मीटर में)

नैनी	37.07 21.02
सिविल लाइंस	25.78
रानीपुर प्रयाग	25.25
सदर तहसील	25.10
न्यू कटरा	25.03
जार्ज टाउन	24.80
सर्किट हाउस	23.88
एडीएकॉलोनी नैनी	23.14
पीपल गांव	23.00
महेशपुर झूंसी	21.45

शहरी क्षेत्र में भूजल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लोगों से अपील है कि भूजल दोहन कम करने के साथ रिचार्ज करने पर भी ध्यान दें, ताकि भविष्य में लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

– रविकांत सिंह,
संयुक्त निदेशक, भूगर्भ विभाग

बिठूर महोत्सव: कवियों के अंदाज-ए- बयां पर श्रोताओं ने जमकर बजाई तालियां

कानपुर। बिठूर महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को सुप्रसिद्ध कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। आर्तकियों से लड़ने वाला मुझे शक्तिमान बना लो, मुझको अपना राम बनाकर जनता को हनुमान बना लो। मशहूर कवि डॉ. हरिओम पंवार ने यह पंक्तियां प्रस्तुत कीं तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए।

आंबेडकरनगर से आए कवि अभय निर्भीक ने वीर रस पर कविता सुनाई, 370 हटा दिया अब पीओके की बारी है, कान खोलकर दुनियां जनता का आह्वान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी ध्यान से सुनो, भारत माता का हरगिज सम्मान नही खोने देंगे। लाइनें सुनकर पूरा पांडाल भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा। दिल्ली से आएं डॉ. प्रवीण शुक्ल ने तू ही मेरी एफबी, तू ही मेरी इंस्टा है सुनाकर लोगों को हंसाया। शबीना अदीब ने अंधेरे की हर एक साजिश यहां नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हो रोशनी का नाम हो जाए... पंक्तियां सुनाईं।

कवि शिवशरण सिंह बंधु ने बहुत उम्मीद करने से उम्मीद टूट जाती है, चलते-चलते लोग सफर हो जाते हैं, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं... सुनाकर गुदगुदाया। हेमंत पांडेय ने मेरठ की घटना का कटाक्ष करते हुए सुनाया कि ये महिलाएं हमें सदैव भ्रम में डाल देती हैं, मूड ठीक हो तो रखती हैं ये दिल में और खराब हो तो ड्रम में डाल देती हैं। शबीना अदीब ने सुनाया अंधेरों की हर एक साजिश नाकाम हो जाए उजाले हर तरफ हो रोशनी का नाम हो जाए। मुकेश श्रीवास्तव ने कविता सुनाई। इस बीच तेज बारिश की वजह से कवि सम्मेलन रोकना पड़ा। कुछ समय बाद फिर से कवियों ने कविता पाठ किया।

जब मेरे शरीर में
रक्त की बूंद हैं,
मैं लड़ूंगी...
कह दो फिरंगियों से
जब तक मेरे शरीर में
रक्त की बूंद है, मैं लड़ूंगी।

जैसे ही रामजानकी इंटर कॉलेज बिठूर के बच्चों ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित लघु नृत्य नाटिका में इस संवाद का मंचन किया, पांडाल में रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारे से गूंज उठा। इसके अलावा महोत्सव में हुए क्विज में सन बीम इंग्लिश स्कूल के उज्ज्वल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मिजार्पुर साढ़ कंपोजिट विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बिठूर के बच्चों ने कविता पाठ किया। कंपोजिट विद्यालय रमईपुर के बच्चों ने योग शो किया। इस मौके पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन, एडीएम वित्त राजेश सिंह, गोल्डन बाबा, वैभव दीक्षित आदि मौजूद रहे। रामायण का संगीतमयी नाट्य रूपांतरण किया प्रस्तुत श्री राम कला केंद्र दिल्ली के कलाकारों ने रामायण का संगीतमयी नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। प्रस्तुति में भगवान राम के जन्म से लेकर सीता अपहरण और रावण वध पर मंचन किया गया। प्रभु श्रीराम का अभिनय राजकुमार शर्मा, माता सीता का अभिनय प्रेरणा और रावण का अभिनय विशाल ने किया।

पहिचान तो गए हुइहो...

बिठूर महोत्सव के दूसरे दिन रिमझिम फुहारों के बीच टीवी और हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने अपने हास्य व्यंग्यों से लोगों को जमकर गुदगुदाया। जैसे ही वह मंच पर आए तो श्रोता खुद ही बोल उठे पहिचान तो गए हुइहो।

अन्नू अवस्थी ने कवियों पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि इतने कवियों के बीच एक कवियत्री न आवै तो इन कवियों का मुंह देखने लायक होता है। कहा कि कवि गांधी जी है तो हम नाथूराम गोडसे है।

लू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करें : एडीएम

संतकबीरनगर। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को एडीएम जय प्रकाश की अध्यक्षता में गर्मी के मौसम में हीट वेव से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पहले से ही सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया। एडीएम जय प्रकाश ने कहा कि गर्मी के मौसम में हीट वेव/लू से बचाव के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाए। गर्मी के मौसम में सुरक्षात्मक उपायों का उचित प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी के मौसम में अधिक तापमान रहने के साथ ही हीट वेव चलने की संभावना है। उन्होंने समस्त अधिकारियों को हीट वेव से बचाव के लिए विभागवार दायित्व के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि जिला आपदा प्रबंधन की ओर से जारी एडवाइजरी में लू से बचाव के उपाय, लक्षण व उपचार आदि के बारे में बताया गया है। सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया ने कहा कि गर्म हवाओं से बचने के लिए खिड़की को रिफ्लेक्टर जैसे एल्युमिनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखें ताकि बाहर की गर्मी को अंदर आने से रोका जा सके। जहां तक संभव हो घर में ही रहें तथा सूरज के ताप से बचें। घर में पेय पदार्थ जैसे लस्सी, छाछ, मट्ठा, बेल का शर्बत, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी या आम का पना इत्यादि का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि अभी आगे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा, इसलिए गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना चाहिए। इस अवसर पर एडीएम न्यायिक चंद्रेश सिंह, एसडीएम मेंहदावल संजीव राय, एसडीएम धनघटा अरुण कुमार, एसडीएम सुनील कुमार, प्रशिक्षु एसडीएम आतिश कुमार सिंह, एसडीएम जनार्दन आदि मौजूद रहे।

जिला अस्पताल: बंद पड़े 10 प्राइवेट वार्ड कोई सुधि लेने वाला नहीं

ड्रेनेज सिस्टम (जल निकासी प्रणाली) सही नहीं होने के कारण प्राइवेट वार्डों को फिर शुरू नहीं किया जा सका है। अगर अब इन्हें शुरू किया गया पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा और कमरों में पानी भर जाएगा। इसके लिए नगर निगम से भी बात की गई थी। फिलहाल शुरू होने की उम्मीद नहीं है।

डॉ. बीपी कौशिक, चिकित्सा अधीक्षक, जिला अस्पताल

मेरठ। पीएल शर्मा जिला अस्पताल के 10 प्राइवेट वार्ड करीब 17 साल से बंद पड़े हैं। कमरों में ताले लटके हुए हैं, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इनके बनने और कई बार किए गए इनके नवीकरण (रिनोवेशन) में शासन के लाखों रुपये खर्च हुए हैं। अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो यह मरीजों के काम आ सकते हैं। इनमें से पांच प्राइवेट वार्ड बच्चा वार्ड के पीछे वाली बिल्डिंग में हैं। टाइल्स लगी हैं। बिजली-पानी की उचित व्यवस्था है, जबकि पांच प्राइवेट वार्ड ब्लड बैंक के बराबर में हैं। इन्हें कार्यालय और सामान आदि रखने में इस्तेमाल किया जा रहा है। बाहर से दिखने में सही लगते हैं मगर अंदर से यह भी खराब होते जा रहे हैं। 17 साल पहले जब ये संचालित थे, तब इनका किराया बेहद सस्ता, महज 135 रुपये दिन था। लोग भर्ती होते थे। प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय 1909 में बना था। यहां रोज 1500 से 2000 लोग इलाज कराने के लिए आते थे।

रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ होली मिलन का आयोजन

झांसी। गत दिनों शुक्रवार को शहर में विभिन्न समाजसेवी संगठनों के तत्वाधान में होली मिलन समारोह के आयोजन किये गये। इस दौरान, फूलों की मनमोहक होली खेली गई और मधुर गीतों पर नृत्य किया। चंदन-गुलाल का तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं।

इसी क्रम में सिद्धेश्वर मंदिर में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के होली मिलन समारोह में फूलों की होली खेली गई। होली के मधुर गीतों पर लोग झूम उठे। मौके पर मंदिर पीठाधीश्वर हरिओम पाठक, लल्लन महाराज, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, शिक्षक विधायक डा. बाबूलाल तिवारी, विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, समिति के अध्यक्ष भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव श्रृंगीऋषि, संतोष सोनी, मुकेश मिश्रा आदि रहे। इधर, पेंशनर्स एसोसिएशन ऑफ रेलवेज झांसी मंडल का होली मिलन समारोह हुआ। होली के गीत, हास्य, व्यंग्य गीत आदि प्रस्तुतियां दी गईं। फूलों की होली खेली गई। ओएस भटनागर, आरपी पाल, पीके भटनागर, मंडल सचिव पीके श्रीवास्तव, शैलेंद्र निगम आदि मौजूद रहे। इधर, भारतीय बौद्ध संघ के कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश जायसवाल, रीता ओझा, अनीता सिंह, कुसुम साहू, प्रेमलता, दीपमाला आदि मौजूद रहीं।

बुंदेली विधाओं को विश्व स्तर पर मंच दिया जाएगा : हरगोविंद कुशवाहा

भंडरा। ग्राम पंचायत भंडरा में पहाड़ किनारे स्थित प्राचीन अंबे गौरी माता मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों द्वारा बुधवार को रंग पंचमी के मौके पर फागोत्सव के चलते राई गायन एवं नृत्य का आयोजन कराया गया। जिसका उद्घाटन राज्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हरगोविंद कुशवाहा, मऊरानीपुर ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह परिहार, जिला पंचायत सदस्य प्रतिपाल सिंह झांकरी, राघवेंद्र सिंह चौहान, भाजपा चुरारा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाहा, जिला प्रतिनिधि सुभाष मौर्य, यज्ञजीत सिंह आदि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम में आधा दर्जन राई नृत्यांगनाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किए, जिसने श्रोताओं का मन मोह लिया। इस दौरान शत्रुघ्न पटेल, पुष्पेंद्र पटेल, लखन पटेल, सत्यनारायण सोनकिया मौजूद रहे।

हिन्दू समुदाय मजबूती से खड़ा है नफरत के खिलाफ

हिन्दू समुदाय नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वह कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों द्वारा ऐसे मामलों की अनदेखी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना विडम्बनापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाते हुए सख्त संदेश देना चाहिए।

हिन्दू समुदाय नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, वह कभी भी नफरत को जड़ नहीं जमाने देंगा। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा सरकारों द्वारा ऐसे मामलों की अनदेखी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई न करना विडम्बनापूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार को भी कड़े कदम उठाते हुए सख्त संदेश देना चाहिए।

अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने को खालिस्तान समर्थकों से जोड़कर देखा जा रहा है। दक्षिण कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स इलाके में स्थित मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए अरैर मन्दिर को क्षति पहुंचाई गयी। माना जा रहा है कि खालिस्तान जनमत संग्रह से पहले साजिश के तहत ये हमला किया गया है। कुछ दिन पहले न्यूयार्क में भी स्वामीनारायण मंदिर पर भी हमला हुआ था। 25 सितंबर को कैलिफोर्निया के स-क्रामेंटो स्थित स्वामीनारायण मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, तोड़फोड़ की गई और उस पर आपत्तिजनक संदेश भी लिख दिए गए हैं। आपत्तिजनक यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा में सक्रिय ऐसे तत्वों को इन देशों की सरकारों द्वारा राजनीति के चलते खुला समर्थन देना एवं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रश्रय दिया जाना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, कब तक खामोश रहा जाये? कैलिफोर्निया में स्वामीनारायण मंदिर पर हुई घटना से पहले लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के गाड़ी के सामने खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसे सामान्य घटना नहीं माना जा सकता। जो खालिस्तान समर्थक विदेश मंत्री के काफिले तक कूद गया, वह सुनियोजित ढंग से हमला भी कर सकता था। निश्चित तौर पर यह ब्रिटिश पुलिस की कोताही एवं लापरवाही है।

खालिस्तानी अलगाववादियों से जुड़े कुछ अराजक तत्वों ने एक बार फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया है, हिन्दुओं वापिस भारत जाओ जैसे आपत्तिजनक संदेश लिखकर मंदिर को क्षति पहुंचायी गई है। हिन्दू मन्दिरों एवं आस्था पर बार-बार हो रहे ये हमने दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। आतंक फैलाने की मंशा से मंदिरों पर हमले की ऐसी घटनाओं का बार-बार होते रहना चिन्ता का सबब है। ऐसे पृथकतावादी तत्व हिंदुओं के खिलाफ विषवमन करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं एवं दवाब बनाना चाहते हैं। भारतीय सांझा संस्कृति में मिलजुलकर रहने वाले समाजों को विभाजित करके घृणा, नफरत एवं द्वेष उत्पन्न करने वाले तत्वों को न केवल बेनकाब करने की जरूरत है बल्कि उन्हें नेस्तनाबूंद किया जाना चाहिए। बात केवल खालिस्तानी अलगाववादियों की नहीं है, मुस्लिम आतंकवादी भी विभिन्न देशों में हिन्दू धर्म, मन्दिर, आस्था एवं संस्कृति पर ऐसे ही हमले करके दहशत फैला रहे हैं।

उस समय खालिस्तानी उग्रवादी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया।

विडंबना यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश की सरकारें ऐसे हमलों व मंदिरों को अपवित्र करने, उनको नुकसान पहुंचाने, अराजक माहौल खड़ा करने की घटनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रखकर आंखें मूंद लेती हैं या कुछ देश कट्टरतावाद के चलते उन देशों के अल्पसंख्यक समुदायों पर तरह-तरह के हमले होने देती है। यह विडम्बना ही है कि जब दूसरे देशों में उनके धर्म के लोगों के पूजा स्थलों पर हमले होते हैं तो उसे धार्मिक आजादी व मानवाधिकारों का संकट बताने लगते हैं, फिर हिन्दू मन्दिरों एवं आस्था पर हो रहे ऐसे हमलों को लेकर दोहरी मानसिकता एवं दोहरा मापदण्ड क्यों? क्यों भेदभावपूर्ण मानसिकता है? निश्चित रूप से ऐसे ही रवैये से भारत के साथ इन देशों के संबंधों में खटास आती है।

ऐसे ही अलगाववादियों के कृकृत्यों व कनाडा सरकार के अलगाववादियों को संरक्षण देने के चलते ही दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर में पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे हमलों के कारण ही दोनों देशों के संबंध बिगड़ चुके हैं। आतंक से जो जन्मती है, वह संस्कृति नहीं होती है, उसमें पाशविकता होती है, उसमें जानवर विद्यमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति, संगठन एवं देश किसी के प्रिय नहीं हो सकते, वे मानवता को त्राण नहीं, संत्रास देते हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कुत्सित कोशिशों की तीव्र निंदा एवं भर्त्सना की है, सवाल यह उठता है कि जब ऐसी आजादी किसी सभ्य समाज के अहसासों से खिलवाड़ करे और दूसरों की धार्मिक आजादी का अतिक्रमण करने लगे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दरअसल, ये घटनाक्रम इन देशों के दोगले मापदंड उजागर करते हैं। दूसरे देशों में सांप्रदायिक असहिष्णुता और कथित भेदभाव के आंकड़े जारी करके दबाव बनाने वाले तथाकथित सभ्य देश अपने क्रियाकलापों से बेनकाब हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में करीब एक दर्जन मंदिरों को अपवित्र करने की कुत्सित कोशिश हुई, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ दिखावे के लिये भी कार्रवाई नहीं की गई। किसी हमले की जांच भी नहीं हुई। जबकि प्रत्येक संप्रदाय की धार्मिक आजादी की रक्षा करना अमेरिकी सरकार का नैतिक दायित्व है। अमेरिका खुद को धर्मनिरपेक्षतावादी एवं मानवाधिकार का हिमायती मानता है। आखिर अमेरिका जैसे शक्तिसंपन्न राष्ट्र में मंदिरों को सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया करायी जाती? बीते साल भी कनाडा में हिंदू महासभा के मंदिर में हमला करके बच्चों व महिलाओं तक को पीटा गया था। लेकिन ट्रूडो सरकार खामोश रही। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी की कहावत के अनुसार ट्रूडो सरकार बिखर गयी, धराशायी हो गयी। निश्चित रूप से पश्चिमी देशों की सरकारों को अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा व गरिमा तय करनी होगी।

लगातार हो रहे इन हमलों के बाद भी हिन्दू समुदाय शांति और करुणा की ही बात करता आया है। पर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक यह सिलसिला चलेगा? क्या अमेरिकी एवं ब्रिटेन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? हाल ही में ब्रिटिश गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ऐसे अतिवादियों के उभार को ब्रिटिश कानून व्यवस्था के लिये खतरा बताया गया था।

आतंक किसी एक देश नहीं, सम्पूर्ण मानवता के लिये गंभीर खतरा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों की अनदेखी की जा रही है। निश्चित तौर पर छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करने से कालांतर में बड़ी हिंसक गतिविधियों को ही प्रश्रय मिलता है। प्रतिबंधित आतंवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस कनाडा सहित कई देशों में लगातार भारत विरोधी अभियान चला रहा है। 17 नवंबर 2024 को न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही अभियान चलाने की कोशिश की गई और भारत विरोधी नारे लगाते हुए खालिस्तान का झंडा लहराया गया। लेकिन न्यूजीलैंड के नागरिकों ने इसका विरोध किया और खालिस्तान समर्थकों के मनसूबों को सफल नहीं होने दिया।

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिये आतंकी संगठन और दुश्मन देश आतंक का सहारा ले रहे हैं।

सरकार की नीति, सशक्त सुरक्षा व्यवस्था, सरकार की सतर्कता के चलते ही आतंकवादी संगठन एवं आतंकवादी अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अधिक सावधान एवं सख्त होने की अपेक्षा है, अन्यथा भारत की सारी प्रगति को आतंकवाद खा जायेगा। क्योंकि लगातार असफलता से खीझे एवं बौखलाये हुए आतंकी कोई-न-कोई नई और अधिक खौफनाक आतंकी घटना को अंजाम देने में जुटे रहते हैं, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अधिक सतर्कता बरतने की अपेक्षा है। दुनिया के शक्तिसंपन्न राष्ट्र भी मंथन करें आतंक रूपी विष और विषमता को समाप्त करने का, शांतिपूर्ण दुनिया निर्मित करने का।

▶ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी खास में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन

शरीर में निर्जलीकरण को रोकने का ओआरएस प्रभावी उपाय

▶ बच्चों के लिए विशेष जरूरी है ओआरएसः डा. प्रदीप खरया

गोरखपुर (जीकेबी)। तेजी से करवट लेते हुए गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी होने से लोग अक्सर निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) का शिकार हो जाते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे बचाव के लिए ओआरएस जीवन रक्षक घोल का सेवन एक प्रभावी उपाय है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी खास में स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन एम्स गोरखपुर की ओर से किया गया। एम्स के सामुदायिक एवं पारिवारिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डा. आनंद मोहन दीक्षित ने कहा कि ओआरएस को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। यह केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। दस्त, उल्टी या अत्यधिक पसीना आने की स्थिति में ओआरएस का सेवन शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट जय शंकर मिश्र ने सभी लाभार्थियों को ओआरएस के पैकेट वितरित किए और इसके सही उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा विभाग के डा. प्रदीप खरया ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि बच्चों में दस्त और उल्टी के कारण ड़िहाइड्रेशन का खतरा अधिक होता है। कई बार खानपान में गडक्ष्बडक्षी या संक्रमण के कारण बच्चों को पतले दस्त होने लगते हैं। अगर बच्चे को बारम्बार दस्त आ रहे हैं, तो तुरंत ओआरएस देना शुरू कर देना चाहिए। सुधार न होने पर तत्काल ड़ाक्टर से संपर्क करना चाहिए।

जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत : नकवी

नई दिल्ली। दल्ली कई वर्षों से जल संकट का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और सीमित जल संसाधनों के कारण पानी की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बना हुआ है। इसके पीछे दिल्ली का पानी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होना है। पानी पर सियासत भी होती है, जो जनता को परेशान करती रही है। दरअसल दिल्ली पानी के मामले में मुख्य तौर पर पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 990 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी की आपूर्ति होती है, जबकि मांग 1250 एमजीडी से अधिक है। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 260 एमजीडी की कमी है, जो गर्मियों में और भी विकराल रूप ले लेती है।

दिल्ली की जल आपूर्ति मुख्यतः यमुना व गंगा नदियों पर निर्भर है, जिनका पानी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के बीच विभाजित है। इन राज्यों की अपनी आवश्यकताएं हैं, जिससे दिल्ली को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। उधर, पानी की कमी के बीच दिल्ली की जल वितरण प्रणाली में लीकेज, अवैध कनेक्शन और टैंकर माफिया जैसी समस्याएं हैं, जो जल आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन सब बातों के बीच दिल्ली में जल स्रोतों की कड़ी में झीलों और तालाबों का संरक्षण और पुनर्जीवन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है। हालांकि, दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां जल संकट को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं। इस कड़ी में पानी का शोधन बढ़ाया है। वर्ष 2015 में दिल्ली की जल शोधन क्षमता लगभग 850 एमजीडी थी। वर्तमान में इसे बढ़ाकर 990 एमजीडी किया गया है और अगले 2-3 वर्षों में इसे 1200 एमजीडी तक ले जाने का लक्ष्य है। वहीं दिल्ली में जल स्रोतों का पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जल वितरण प्रणाली में सुधार के लिए लीकेज को कम करने 100 प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

उधर पिछले पांच वर्षों में भूजल के माध्यम से आपूर्ति में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020 में भूजल के माध्यम से 86 एमजीडी पानी की आपूर्ति हो रही थी, जो 2024 में बढ़कर 135 एमजीडी हो गई है।

सिटीजन फ्रंट फॉर वाटर डेमोक्रेरी के संयोजक एसए नकवी ने दिल्ली में बढ़ते पेयजल संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर भविष्य में और गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की बढ़ती आबादी और जल स्रोतों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे पानी की बचत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

नलों से पानी बहने देना, गाड़ियों की धुलाई में अत्यधिक पानी का उपयोग और पाइप लीकेज जैसी समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को भी जल संकट से निपटने के लिए ठोस योजनाएं गंभीरता से लागू करनी होंगी। वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों को अपनाना आवश्यक है।

स्टेट ऑफ इंडियाज बड्र्स (एसओआईबी) रिपोर्ट 2023 का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि गत 25 वर्षों के दौरान गौरैया की आबादी कुल मिलाकर काफी स्थिर रही है। हालांकि भारत में हाउस स्पैरो की संख्या कम होने की आम धारणा है।

पर्यावरण को गौरैया की आज भी जरूरत

गौरैया छोटे, फुतीर्ले पक्षी होते हैं जो 4 से 7 इंच तक लम्बे होते हैं। उनके गोल, मोटा शरीर और छोटी मजबूत चोंच होती हैं जो खुले बीजों को तोड़ने के लिए उपयुक्त होती हैं। उनके पंखों पर धारियां या गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह हल्की भूरे रंग या सफेद रंग में होती है। इसके शरीर पर छोटे-छोटे पंख और पीली चोंच व पैरों का रंग पीला होता है।

गौरैया मनुष्य के आसपास रहना पसंद करती है। यह लगभग हर तरह की जलवायु पसंद करती है पर पहाड़ी स्थानों में कम दिखाई देती है। शहरों, कस्बों, गांवों, और खेतों के आसपास यह बहुतयात से पाई जाती है। नर गौरैया के सिर का ऊपरी भाग नीचे का भाग और गालों पर पर भूरे रंग का होता है। गला चोंच और आंखों पर काला रंग होता है और पैर भूरे होते है। मादा के सिर और गले पर भूरा रंग नहीं होता है। नर गौरैया को चिड़ा और मादा चिड़ी या चिड़िया भी कहते हैं।

गौरैया पक्षियों के पैसर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है जो विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाती है। आरम्भ में यह एशिया, यूरोप और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी। लेकिन मानवों ने इसे विश्वभर में फैला दिया है। यह मनुष्यों के समीप कई स्थानों में रहती हैं। पिछले कुछ सालों में शहरों में गौरैया की कम होती संख्या पर चिन्ता प्रकट की जा रही है। आधुनिक स्थापत्य की बहुमंजिली इमारतों में गौरैया को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती।

प्रति वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लिए हमारे आस पास का माहौल बेहतर करना है। गौरैया चिड़िया को घरेलू चिड़िया भी कहा जाता है। क्योंकि यह घरों के अंदर भी घोसले बनकर रह लेती है। ये मानव और प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि यह कीड़ों को खाती है जिससे कीड़े पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा धर्मशास्त्र के मुताबिक गौरैया का आपकी छत पर आना आपके लिए शुभ होता है। जानकारो का कहना हैं कि यह चिड़िया शांति और सदभावना का संदेश लेकर आती है।

हमारे घर के आंगन में सबसे बड़ी संख्या में एक छोटी चिड़िया देखने को मिलती है जिसे हम गौरैया कहते हैं। यह चिड़िया बचपन से ही हमारी साथी बन जाती है। जब बच्चा कुछ समझने लगता है तो सर्वप्रथम उसको जो पक्षी देखने को मिलता है वह नन्ही चिड़िया यानी गौरैया होती है। यह नन्ही चिड़िया बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है और अपनी मीठी आवाज से उन्हें आकर्षित करती रहती है। गौरैया बच्चों के हाथ से कई बार खाने की वस्तु भी झपटकर ले जाती है। छोटे बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और वह फुर्र से उड़कर ऊपर बैठ जाती है। गांव देहातों में यह आज भी देखने को मिल जाता है। मगर शहरों में अब ऐसा नजारा शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा।

कभी बड़ी संख्या में हमारे साथ रहने वाली गौरैया अब धीरे-धीरे बहुत कम होती जा रही है। मगर जीवन की भाग दौड़ में किसी का ध्यान इनकी घाटी संख्या की तरफ नहीं जा रहा है। बच्चों की सबसे नजदीकी मित्र गौरैया जिस तेजी से कम होती जा रही है उससे लगता है आने वाले समय में यह कहीं विलुप्त ना हो जाए। इसलिए हम सबको मिलकर गंभीरता से ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे गौरैया को संरक्षण मिल सके और उनकी संख्या में फिर से बढ़ोतरी प्रारंभ हो सके।

आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में घर-आंगन में चहकने-फुदकनेवाली छोटी सी प्यारी चिड़िया गौरैया की आबादी में 60 से 80 फीसदी तक की कमी आई है। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बड्र्स' ने भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में

अनुसंधानकताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में डाला था। वहीं आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक गौरैया की आबादी में करीब 60 फीसदी की कमी आई है। यह कमी ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में हुई है। पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के अनुसार गौरैया की आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है। जब हम स्टेट ऑफ इंडियाज बड्र्स (एसओआईबी) रिपोर्ट 2023 का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि गत 25 वर्षों के दौरान गौरैया की आबादी कुल मिलाकर काफी स्थिर रही है। हालांकि भारत में हाउस स्पैरो की संख्या कम होने की आम धारणा है। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर दिल्ली सरकार ने 2012 और बिहार सरकार ने 2013 से गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित कर रखा है।

कभी हमारे घर-आंगन में गिरे अनाज को खाने गौरैया फुर्र से आती थी और दाना चुगकर उड़ जाती थी। हालांकि गांवों में आज भी कई घरों में गौरैया आ रही है। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में आहार की कमी, बढ़ता आवासीय संकट, कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन-शैली में बदलाव, प्रदूषण और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जाता रहा है।

गौरैया की संख्या में कमी के पीछे बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग को माना जा रहा है। गौरैया अपने बच्चे को फसल, साग-सब्जी, फलों में लगनेवाले कीड़े को खिलाती है। इससे गौरैया के बच्चे को भरपूर प्रोटीन मिलता है। बच्चा अनाज खा नहीं सकता है लेकिन जिस तरह से फसल-सब्जी-फल-अनाज में कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा है। उससे उनके बच्चों को सही आहार मिल पाने में परेशानी हो रही है। फसल और साग-सब्जी में बेतहाशा कीटनाशक के प्रयोग ने कीड़ों को मार डाला है। ऐसे में गौरैया अपने बच्चे को पालने के दौरान समुचित आहार यानी प्रोटीन नहीं दे पाती है और बच्चे कमजोर हो जाते हैं।

गौरैया के प्रजनन के लिए अनुकूल आवास में कमी को भी इसकी संख्या में कमी का एक कारण माना जा रहा है। कच्चे घरों का तेजी से कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने से शहरों में इनके प्रजनन के लिए अनुकूल आवास नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि एक ही शहर के कुछ इलाकों में ये दिखती है तो कुछ में नहीं। गौरैया संरक्षण में जुड़े लोग कृत्रिम घर बनाकर गौरैया को प्रजनन के लिए आवास देने की पहल चला रहे हैं। इसमें गौरैया अंडे देने के लिए आ भी रही हैं।

जहां तक गौरैया का सवाल है यह इन्सानों की दोस्त तथा किसानों की मददगार है। गौरैया इन्सान के साथ रहते हुए उन्हें सुख-शांति प्रदान करती हैं। बच्चों का बचपन इसके साथ खेलते हुए गुजरता है। लेकिन हम इन्सानो ने ही इसे अपने से दूर कर दिया है। भारत में पक्षियों की कुल मिलाकर 1250 प्रजातियां हैं। जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिसमें गौरैया का भी नाम शामिल है।

गौरैया का सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा लेती है। जिससे किसान की फसल खराब होने से बच जाती हैं। गौरैया अपना घौंसला इंसानों के करीब बनाती है। इससे उनके घौंसले उजाड़ दिए जाते हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण भी इन पक्षियों के लिए मुसीबत है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से यह समझने की कोशिश करें कि छोटी सी गौरैया हमारे जीवन के लिए कितनी अहम है। ऐसे में उसकी रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 2025 में विश्व गौरैया दिवस की थीम 'प्रकृति के नन्हे दूतों को श्रद्धांजलि' है। यह थीम पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में गौरैया की भूमिका पर प्रकाश डालती है और संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करती है।

घूँघट की बगावत

23 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

अगर हम तालाबों और बावड़ियों को सिर्फ.पानी जमा करने की जगह समझते हैं, तो शायद हम उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। ये सिर्फ.जल-स्रोत नहीं, बल्कि सदियों की कहानियों, रहस्यों, परंपराओं और लोककथाओं के ज़िंदा गवाह हैं। पुराने तालाब और बावड़ियाँ इतिहास की किताब के वह पन्ने हैं, जिन पर समय की बूंदें टपकी हैं। अब जब हम पानी के संकट से जूझ रहे हैं, तब इन प्राचीन जल स्रोतों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। आधुनिक टैंकर और बोरवेल के भरोसे रहने की बजाय अगर हम फिर से बावड़ियों और तालाबों को ज़िंदा करें, तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी तारीफ करेंगी (और शायद तालाबों के किनारे बैठकर अपनी नई कहानियाँ रचेंगी) । तालाब और बावड़ियाँ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का अभिन्न अंग रही हैं। वे न केवल जल-संग्रहण के साधन थे, बल्कि समाज के सामूहिक जीवन, कला, स्थापत्य और आध्यात्मिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। आज के दौर में जल संकट एक गंभीर समस्या बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित शहरीकरण और भूजल के अत्यधिक दोहन ने पानी की उपलब्धता को प्रभावित किया है। ऐसे में प्राचीन जल संरचनाओं, जैसे तालाब और बावड़ियों का पुनरुद्धार और संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। तालाब और बावड़ियाँ हमारे पूर्वजों की अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। वर्तमान जल संकट को देखते हुए, इनका पुनरुद्धार और संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यह न केवल जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी बचाएगा। यदि हम सामूहिक रूप से प्रयास करें, तो इन ऐतिहासिक जल स्रोतों को फिर से जीवंत किया जा सकता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है।

अतीत की गोद में सोए तालाब और बावड़ियाँ: बस पानी ही नहीं, कहानियों का खजाना

अतीत की यादों में समाये तालाब और बावड़ियाँ केवल जल-स्रोत नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी थे। ये जल संरचनाएँ प्राचीन भारतीय समाज की जल प्रबंधन प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थीं, जो हमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और पर्यावरण के प्रति उनके सम्मान की याद दिलाती हैं। तालाब गाँवों और नगरों के जीवन का केंद्र हुआ करते थे। वर्षा जल संचयन, कृषि सिंचाई, मवेशियों की प्यास बुझाने और सामाजिक मेलजोल के लिए इनका उपयोग किया जाता था। तालाबों के किनारे मंदिर, घाट और धर्मशालाएँ बनाई जाती थीं, जहाँ लोग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने आते थे। कई स्थानों पर ये तालाब त्योहारों और मेलों का केंद्र भी बनते थे। प्राचीन भारत में जल को केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि पूजनीय तत्व माना जाता था। इसलिए, जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक और कलात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। राजाओं, रानियों, समाजसेवियों और मंदिर समितियों ने बड़े पैमाने पर तालाब और बावड़ियों का निर्माण कराया। इनका उद्देश्य जल संचयन के साथ-साथ सामाजिक समृद्धि और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देना भी था। पुराने तालाबों के पास बैठकर अगर आप जरा ध्यान दें, तो आपको उनकी लहरों में इतिहास की हलचल महसूस होगी। कभी ये गाँव-शहरों की जान हुआ करते थे। गाँवों में तालाब के किनारे बुजुर्ग किस्से सुनाते, बच्चे खेलते और महिलाएँ पानी भरते हुए अपनी कहानियों की गहराइयों में खो जातीं। ये सिर्फ.जल संरचनाएँ नहीं थीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल के सबसे अहम केंद्र थे।

बावड़ियाँ विशेष रूप से स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण थीं। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता था कि गर्मी के मौसम में भी पानी ठंडा बना रहे। राजस्थान और गुजरात में बनी बावड़ियाँ आज भी अपनी जटिल नक्काशी, मेहराबों, स्तंभों और मूर्तियों के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बावड़ियाँ (सीढ़ीदार कुएँ) विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य भारत में लोकप्रिय थीं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में अनेक प्राचीन बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिनकी स्थापत्य कला अद्भुत होती थी। ये केवल जल संग्रहण का साधन नहीं थीं, बल्कि गर्मियों में ठंडी छाँव में बैठने और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल का कार्य भी करती थीं। प्रसिद्ध बावड़ियों में चाँद बावड़ी (अभनेरी, राजस्थान) और रानी की वाव (पाटण, गुजरात) अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। तालाब और बावड़ियाँ जल संचयन और भूजल पुनर्भरण (ऋ॒ङ्ख॒ल्लद्बिंशी१ फ्रूँशै) का महत्त्वपूर्ण माध्यम थीं। जलवायु परिवर्तन और जल संकट के इस दौर में यदि हम इन पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करें, तो यह न केवल भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि बाढ़ जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक होगा। आधुनिक शहरीकरण और बढ़ती उपेक्षा के कारण कई तालाब और बावड़ियाँ सूख चुके हैं या अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। कई जल स्रोत गंदगी और कचरे से भर चुके हैं, जिससे न केवल उनका ऐतिहासिक महत्त्व समाप्त हो रहा है, बल्कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सरकार और स्थानीय समुदायों को मिलकर पुराने जल स्रोतों की सफाई करनी चाहिए। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए ठोस कानूनी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। गांवों और शहरों में सामुदायिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोग इन धरोहरों को संजोने में सक्रिय भाग लें। इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे लोग इनके महत्त्व को समझें और संरक्षण के लिए प्रेरित हों।

वर्तमान में कई शहर और गाँव पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है क्योंकि वर्षा जल का संचयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। यदि तालाबों और बावड़ियों को पुनर्जीवित किया जाए, तो वे भूजल को फिर से भरने में मदद कर सकते हैं, जिससे नदियों और कुओं का जल स्तर संतुलित रहेगा। कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। यदि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए, तो वर्षा जल को संग्रहित करके सूखे के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, यह जल निकासी की भी एक प्रभावी प्रणाली बन सकती है। तालाब और बावड़ियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। ये जलाशय पक्षियों, मछलियों और अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं। यदि इन्हें पुनर्जीवित किया जाए, तो जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकता है। प्राचीन बावड़ियाँ और तालाब न केवल जल संरचनाएँ हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। आज कई बावड़ियाँ और तालाब उपेक्षित पड़े हैं या कचरे से भर चुके हैं। इन्हें साफ कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यदि तालाब और बावड़ियों को फिर से उपयोग में लाया जाए, तो ग्रामीण और शहरी समुदायों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। वे खेती, पशुपालन और दैनिक जीवन में जल संकट से बच सकेंगे। इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि वे स्वयं इनके संरक्षण की जिम्मेदारी लें।

तालाब और बावड़ियाँ हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता और कुशल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण हैं। यदि हम इन्हें पुनर्जीवित करें, तो यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था—तीनों के लिए लाभकारी होगा। हमें अपने अतीत से सीख लेते हुए जल संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इन अद्भुत संरचनाओं का लाभ उठा सकें। आज के समय में कई तालाब और बावड़ियाँ उपेक्षा के कारण सूख गए हैं या गंदगी से भर गए हैं। शहरीकरण और जल संकट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इन पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार आवश्यक हो गया है। कई जगहों पर लोग और संगठन इन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तालाब और बावड़ियाँ हमारे अतीत की वह धरोहर हैं, जो हमें जल संरक्षण और सामुदायिक जीवन की महत्त्वपूर्ण सीख देती हैं। इनका संरक्षण हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संकट से निपटने में सहायक हो सकता है।

—डॉ. सत्यवान सौरभ

देश की भाषिक योजना और हिंदी

विजय गर्ग

देश में आजादी का आंदोलन और हिंदी की स्वीकार्यता दोनों कार्य समांतर चल रहे थे। उस समय अंग्रेजों और अंग्रेजी दोनों के बरक्स हिंदी एक औजार की तरह कार्य कर रही थी। यही कारण था कि बाद में हिंदी स्वतंत्र भारत की भाषिक अभिव्यक्ति बनी। इसके पीछे सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, देशभर के स्वतंत्रता सेनानी इस मत के साथ कार्य कर रहे थे कि देश के लोकतंत्र की भाषा हिंदी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदी को केंद्रीय स्तर पर राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि इसके साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके मूल में अंग्रेजी की विरासत और कुछ छिटपुट हिंदी विरोध था। मगर तब से और आज तक धरातल पर बहुत कुछ बदल चुका है। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकले निष्कर्ष को देखें, तो हिंदी विरोध के गुब्बारे में सुई जमीनी स्तर से चुभाई जा रही है। इसलिए राजनीति में नकारात्मक भाषाई मुद्दों को चुनने का ढर्रा अब बदल देना चाहिए। निराशा की बात है कि ऐसा नहीं रहा और दिनों-दिन इस तरह के मुद्दे उठाए जाने लगे हैं।

दरअसल, हिंदी बोलने वालों की जो जनसंख्या वर्ष 2001 में थी, उसमें 2011 तक अखिल भारतीय स्तर पर 25.19 फीसद की वृद्धि हुई, लेकिन यही विस्तार किसी पूर्ण राज्य के रूप में तमिलनाडु में सबसे ऊपर है, जो अब 107.62 फीसद है। आगे यह केरल में 96.80, गोवा में 95.40, गुजरात में 78.53 और कर्नाटक में 49.71 फीसद है। हिंदी- विस्तार का यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश 23.86 फीसद, बिहार र में 33.08 और मध्यप्रदेश में 2.15 फीसद है। गौरतलब है कि यह क्षेत्र कथित रूप से हिंदी प्रदेश है और यहां इन दस वर्षों के अंतराल में जनसंख्य के कुल विस्तार वाले फीसद की अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। लिहाजा, धारणा से विपरीत हिंदी का मूल विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में अधिक हुआ है, जहां जहां परंपरागत रूप हिंदी का प्रभाव नहीं माना गया है और उसमें भी तमिलनाडु सबसे ऊपर है। गौरतलब है वहां हिंदी को थोपा नहीं गया है, हिंदी- विरोध तो वहां की राजनीति का केंद्रीय तत्त्व है। दरअसल, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आज अंतरराज्यीय रोजगार, शिक्षा और मनोरंजन आदि की चाहत में लोगों ने हिंदी सीखी है या इन्हीं कारणों से विस्थापन हुआ है। यदि हिंदी को थोपना होता, तो यह संविधान की मूल मंशा के अनुरूप आज देश की अनिवार्य राजभाषा होती, लेकिन यह सच्चाई किसी से नहीं छिपी है कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी सरकारी कामकाज की भाषा स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी ही है। जाहिर है कि हिंदी अपनी जमीन से आगे बढ़ रही है, ऊपर से थोपी नहीं गई है।

इस क्रम में हिंदी को लेकर कुछ बने बनाए भ्रम से देश जितना जल्दी जल्दी निकल जाए, तो अच्छा होगा। सर्वप्रथम तो यही कि 'हिंदी पट्टी' जैसी कोई चीज वास्तविक धरातल पर नहीं है। यह सिर्फ ग्रियर्सन (1928) द्वारा प्रस्तावित 'हिंदी बेल्ट' का अनुवाद भर है, जिसे रामविलास शर्मा आदि सरीखे विद्वानों ने हिंदी में जड़भूत कर दिया। जिस बड़े क्षेत्र को ग्रियर्सन ने 'हिंदी बेल्ट' कहा था, उसी में से बिहार को 'बिहारी भाषा' वाला क्षेत्र बताया था। आज अगर इस भाषा को खोजा जाएगा, तो न तो वास्तव में कोई 'बिहारी भाषा' का अस्तित्व है और न ही 'हिंदी बेल्ट' का वास्तव में इस पट्टी में हिंदी से अधिक प्यार पाने वाली दूसरी सैकड़ों भाषाएं हैं और ये सभी लोग हिंदी को उसी व्यावहारिकता के धरातल पर खड़ा होकर स्वीकार करते हैं, जैसे देश के दूसरे हिस्सों के लोग।

गौरतलब है कि जिस कथित हिंदी पट्टी को हिंदी का ज्ञाता समझ लिया जाता है, वहां हिंदी को अलग से सीखा जाता है। यहां दूर-दराज के क्षेत्रों में आज भी हिंदी उसी तरह है, जैसे बांग्ला, असमिया और गुजराती आदि हो सकती है। यहां तक कि हिंदी का प्रांतीय स्वरूप अपने आप में भिन्न है, जो हिंदी के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। दूसरी तरफ आज देश में हिंदी 5 नाम पर घोषित सरकारी-गैरसरकारी नौकरियों का अखिल भारतीयकरण तेजी से हुआ है। अब देश को जोड़ने, चलाने और जातीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संवाहक भाषाओं की जरूरत हमेशा रहेगी और इसमें हिंदी सर्वाधिक उपयोगी है। समाज खैर, लोकतंत्र में किसी को इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह देश और समाज का एकमेव निर्धारक बन जाए।

भाषाएं बहुभाषिक के लोकतंत्र की नियामक होती हैं। अगर अंग्रेजी का शक्तिशाली होना भारतीय रतीय लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, तो इसकी संभावना हिंदी के साथ भी बनी रहेगी। मगर हिंदी और अंग्रेजी की आपस में हिंदी निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी रही है। इसलिए भी अपने इतिहास से ही हिंदी ने समायोजन पर जोर दिया है, बहिष्कार पर नहीं। यही कारण है कि इसमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी आदि के सैकड़ों शब्द सहज स्वीकृत हैं और यही इसकी शक्ति है, जिस–ासे इसने अपना रास्ता खुद बनाया और आगे भी बनाएगी तथा भारतीय बहुभाषिकता के मूल चरित्र की रक्षा करेगी, जिसमें देश की सभी भाषाएं शामिल हैं। इसका सबसे उदाहरण आज भोजपुरी को लेकर देखा जा सकता है।

सुनहरा लम्हा : धरती पर लौटीं सुनीता विलियम्स

नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, जो पिछले नौ महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (क्रर) पर थे, आज सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद से उन्होंने मेक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग के स्टारलाइनर के साथ परीक्षण उड़ान के लिए अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि, स्टारलाइनर में तकनीकी खामी के कारण उनकी वापसी में देरी हुई, जिससे वे नौ महीने तक क्रर पर रहे। उनकी वापसी के लिए स्पेसएक्स का क्रू-10 मिशन लॉन्च किया गया था, जिसने सफलतापूर्वक उन्हें धरती पर वापस लाया। वापसी के बाद, दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो लंबे समय तक भारहीनता में रहने के बाद सामान्य प्रक्रिया है। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा, बल्कि इससे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के प्रभावों को समझने में भी मदद मिलेगी। इससे नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों, जैसे कि मंगल पर मानव मिशन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी। सुनीता विलियम्स की यह वापसी अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मिशन भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा और अंतरिक्ष यान तकनीक के सुधार में सहायक सिद्ध होगा। सुनीता विलियम्स और उनके जैसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियाँ अब दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर रही हैं, जिनमें अंतरिक्ष में रहने के नए तरीके, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण की संभावनाएँ और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने की रणनीतियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, स्टारलाइनर जैसी तकनीकों में सुधार कर, अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जाएगा। अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति को और विस्तारित करने के लिए वैज्ञानिक शोध जारी रहेंगे, जिससे भविष्य में मंगल और उससे आगे की यात्राएँ संभव हो सकेंगी। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका भारत से गहरा जुड़ाव रहा है। उनके पिता भारतीय मूल के हैं और उन्होंने कई बार भारत के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान की बढ़ती उपलब्धियों के बीच, सुनीता विलियम्स एक प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं। इसरो (क्रफ्ह) भी अब मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इसरो ने हाल ही में गगनयान के लिए प्रमुख परीक्षण पूरे किए हैं और आने वाले वर्षों में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियाँ न केवल भारतीय वैज्ञानिकों बल्कि देश के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी सफलता यह दिखाती है कि भारतीय मूल के लोग वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भविष्य में, इसरो और नासा के बीच सहयोग बढ़ सकता है, जिससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी। सुनीता विलियम्स न केवल एक उत्कृष्ट अंतरिक्ष यात्री हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं। उनका सफर यह दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विज्ञान के प्रति जुनून कैसे किसी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है कि वे अंतरिक्ष अनुसंधान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें।

फागुन में यूं प्यार से...

होली के त्यौहार में, ऐसी उठे तरंग।
तन-मन में जो प्यार की, भर दे खूब उमंग॥
आँगन-आँगन रंग हो, हो रंगीला फाग।
बैर-भाव को छोड़कर, मिलें सभी के राग॥
झूम उठे उल्लास से, क्या बूढ़े क्या बाल।
उड़े खूब इस फाग में, सौरभ रंग गुलाल॥
सड़क-गली हर चौक पर, मचे फाग की धूम।
रार बैर की छोड़कर, राग प्रीत ले चूम॥
होली के त्यौहार में, इतनी तो हो बात।
सबके गालों को मिले, रंगों की सौगात॥
आते होली फाग यूं, देते हैं सन्देश।
प्रेम परस्पर दे सदा, मिटे हृदय से क्लेश॥
फागुन में यूं प्यार से, गा होली के गीत।
पुष्प खिले बस चाह के, होकर के मनमीत॥

-प्रियंका सौरभ

तलाक की भेंट चढ़ते 'तेरे मेरे सपने'

आज के दौर में प्रेम विवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही तलाक की दर भी बढ़ती जा रही है। जहाँ प्रेम विवाह को प्रेम, स्वतंत्रता और आपसी समझ का प्रतीक माना जाता था, वहीं तलाक के बढ़ते मामलों ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी सिर्फ.दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि उनके सपनों, उम्मीदों और भावनाओं का एक संगम होती है। जब दो लोग प्रेम विवाह करते हैं, तो वे भविष्य के कई सुनहरे सपने बुनते हैं—साथ मिलकर जीने के, खुशियाँ बाँटने के और एक खूबसूरत सफर तय करने के। लेकिन जब यह सफर तलाक की कगार पर पहुँचता है, तो सबसे पहले कुचले जाते हैं 'तेरे मेरे सपने'। शादी से पहले जो जोश, उत्साह और अपनापन होता है, वह धीरे-धीरे कई कारणों से फीका पड़ने लगता है। छोटी-छोटी गलतफहमियाँ, अहंकार की दीवारें और बदलती प्राथमिकताएँ उन सपनों को मिटाने लगती हैं, जिन्हें कभी दोनों ने मिलकर संजोया था।

शादी से पहले एक-दूसरे के लिए जो सपने देखे जाते हैं, वे हक ीकत की ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबने लगते हैं। जब सपनों की दिशा अलग-अलग हो जाती है, तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। प्रेम सम्बंध में अक्सर लोग अपने साथी को एक आदर्श रूप में देखते हैं, लेकिन शादी के बाद जब वास्तविकता सामने आती है, तो असंतोष उत्पन्न हो सकता है। एक सफल विवाह के लिए संवाद बहुत जरूरी होता है। यदि जीवनसाथी एक-दूसरे की बातों को समझने और सुनने में असमर्थ होते हैं, तो रिश्ते में दरार आ सकती है। कई बार शादी के बाद आर्थिक दबाव और ज़िम्मेदारियों को निभाने में कठिनाइयाँ आने लगती हैं, जिससे मतभेद बढ़ सकते हैं। प्रेम विवाह में कई बार परिवार और समाज का विरोध झेलना पड़ता है। यदि दंपति मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तो यह तनाव उनके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी एक साथी का व्यवहार संदेहास्पद होता है या अविश्वास उत्पन्न होने लगता है, तो यह तलाक का कारण बन सकता है। शादी के बाद जब दोनों व्यक्तियों की प्राथमिकताएँ बदलने लगती हैं और यदि उनकी सोच मेल नहीं खाती, तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। आधुनिक समय में करियर को प्राथमिकता देने से वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है। कई बार साथी एक-दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने लगते हैं, जिससे मतभेद बढ़ते हैं। आत्मसम्मान और अहंकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। ₹कौन ज्यादा सही है?₹ यह सवाल रिश्ते को भीतर से खोखला करने लगता है और सपने टूटने लगते हैं।

केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि समान विचारधारा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, करियर लक्ष्य और जीवनशैली को ध्यान में रखकर जीवनसाथी का चुनाव करें। हर समस्या पर खुलकर बात करें और अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। शादी से पहले और बाद में एक-दूसरे से व्यावहारिक अपेक्षाएँ रखें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास होती है। अपने साथी के प्रति निष्ठावान रहें और पारदर्शिता बनाए रखें। हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं। किसी भी समस्या का समाधान जल्दबाजी में न निकालें, बल्कि धैर्यपूर्वक विचार करें। कभी-कभी परिवार और करीबी दोस्तों से सलाह लेना भी रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। यदि रिश्ते में समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो विवाह विशेषज्ञ या काउंसलर से मार्गदर्शन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शादी के बाद भी एक-दूसरे के सपनों को समझें और उन्हें साथ मिलकर पूरा करने का प्रयास करें। हर छोटी-बड़ी बात पर चर्चा करें, अपने साथी की भावनाओं को समझें और अपनी बात को सही तरीके से सामने रखें। शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सपनों का त्याग कर दिया जाए। एक-दूसरे को सहयोग दें ताकि व्यक्तिगत इच्छाएँ पूरी हो सकें। जब रिश्ते में अहंकार आ जाता है, तो प्रेम कम होने लगता है। इसलिए हर स्थिति में प्रेम को प्राथमिकता दें। अगर लगने लगे कि रिश्ता बोझ बन रहा है, तो कुछ समय साथ बिताएँ, घूमने जाएँ, पुरानी यादों को ताजा करें और रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करें। प्रेम विवाह में तलाक की बढ़ती दर चिंताजनक है, लेकिन इसे रोका जा सकता है यदि दंपति आपसी समझ, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। शादी सिर्फ.प्रेम पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें सम्मान, जिम्मेदारी और परिपक्वता का होना भी जरूरी है। सही सोच और व्यवहार अपनाकर प्रेम विवाह को सफल और खुशहाल बनाया जा सकता है। तलाक सिर्फ. कानूनी अलगाव नहीं होता, यह उन सपनों की मौत भी होती है जो कभी दो लोगों ने मिलकर देखे थे। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी है कि प्रेम, विश्वास और समझदारी को बनाए रखा जाए। क्योंकि अगर 'तेरे मेरे सपने' बिखर गए, तो सिर्फ.दो दिल नहीं टूटेंगे, बल्कि दो ज़िंदगियाँ भी अधूरी रह जाएँगी। प्रेम विवाह में तलाक की दर अधिक होने का कारण गलत अपेक्षाएँ, कम सहनशीलता, पारिवारिक समर्थन की कमी और संवाद की कमी है। लेकिन सही समझदारी और परिपक्वता से इसे रोका जा सकता है। शादी सिर्फ.प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और आपसी सहयोग से सफल होती है।

-प्रियंका सौरभ

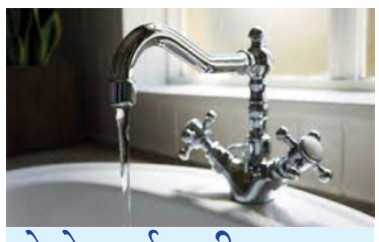

छोड़ो व्यर्थ पानी बहाना...

बारिश को अब आने दो।
तपती गर्मी जाने दो॥

छोड़ो व्यर्थ पानी बहाना,
जीवन को बच जाने दो॥

ये बादल भी कुछ कह रहे।
इनको मन की गाने दो॥

कटते हुए पेड़ बचाओ।
शुद्ध हवा कुछ आने दो॥

पंछी क्या कहते है सुन लो।
उनको पंख फैलाने दो॥

फोटो में ही लगते पौधे।
सच को बाहर लाने दो॥

होती कैसे धरा प्रदूषित।
सबको पता लगाने दो॥

पौध लगाकर पानी दे हम।
सच्चा धर्म निभाने दो॥

चल चुकी है बहुत आरिया।
धरती कुछ बच जाने दो॥

कैसे अब हरियाली होगी।
सौरभ प्रश्न उठने दो॥

झुलस रही पावन धरती पर।
हरियाली तुम आने दो॥

-प्रियंका सौरभ

घूँघट की बगावत

23 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

ट्रंप के टैरिफ निर्णयों का भारत पर प्रभाव

अमेरिका में उपभोक्ता आधारित उत्पादों का आयात अधिक मात्रा में होता है और अब अमेरिका चाहता है कि इन उत्पादों का उत्पादन अमेरिका में ही प्रारम्भ हो ताकि इन उत्पादों का अमेरिका में आयात कम हो सके। दक्षिण कोरीया, जापान, कनाडा, मेक्सिको आदि जैसे देशों की अर्थव्यवस्था केवल कुछ क्षेत्रों पर ही टिकी हुई है अतः इन देशों पर अमेरिका में बदल रही नीतियों का अधिक विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जबकि भारत एक विविध प्रकार की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः भारत को कुछ क्षेत्रों में यदि नुक्सान होगा तो कुछ क्षेत्रों में लाभ भी होने की प्रबल सम्भावना है। संभवतः अमेरिका ने भी अब यह एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि भारत के कृषि क्षेत्र को टैरिफ युद्ध से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि भारत के किसानों पर इसका प्रभाव विपरीत रूप से पड़ता है। और, भारत यह किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा कि भारत के किसानों को नुक्सान हो। डेरी उत्पाद एवं समुद्रीय उत्पादों में भी आवश्यक खाने पीने की वस्तुएं शामिल हैं। भारत अपने देश में इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इन उत्पादों के आयात पर टैरिफ लगाता है, ताकि अन्य देश सस्ते दामों पर इन उत्पादों को भारत के बाजार में डम्प नहीं कर सकें। साथ ही, भारत में मिडल क्लास की मात्रा में वृद्धि अभी हाल के कुछ वर्षों में प्रारम्भ हुई है अतः यह वर्ग देश में उत्पादित सस्ती वस्तुओं पर अधिक निर्भर है, यदि इन्हें आयातित महंगी वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो वह इन्हें सहन नहीं कर सकता है। अतः यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को सस्ते उत्पाद उपलब्ध करवाए। अन्यथा, यह वर्ग एक बार पुनः गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। भारत ने मुद्रा स्फीति को भी कूटनीति के आधार पर नियंत्रण में रखने में सफलता प्राप्त की है। रूस, ईरान, अमेरिका, इजराईल, चीन, अरब समूह आदि देशों के साथ अच्छे सम्बंध रखकर विदेशी व्यापार करने में सफलता प्राप्त की है। जहां से भी जो वस्तु सस्ती मिलती है भारत उस देश से उस वस्तु का आयात करता है। इसी नीति पर चलते हुए, कच्चे तेल के आयात के मामले में भी भारत ने विभिन्न देशों से भारी मात्रा में छूट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है और ईंधन के दाम भारत में पिछले लम्बे समय से स्थिर बनाए रखने में सफलता मिली है।

अमेरिका में दिनांक 20 जनवरी 2025 को नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ली गई शपथ के उपरांत ट्रम्प प्रशासन आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले बहुत तेज गति से ले रहा है। इससे विश्व के कई देश प्रभावित हो रहे हैं एवं कई देशों को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अंततः आगे आने वाले समय में इन फैसलों का प्रभाव इन देशों पर किस प्रकार होगा। ट्रम्प प्रशासन अमेरिका में विभिन्न उत्पादों के हो रहे आयात पर टैरिफ की दरों को बढ़ा रहा है क्योंकि इन देशों द्वारा अमेरिका से आयात पर ये देश अधिक मात्रा में टैरिफ लगाते हैं। चीन, कनाडा एवं मेक्सिको से अमेरिका में होने वाले विभिन्न उत्पादों के आयात पर तो टैरिफ को बढ़ा भी दिया गया है। इसी प्रकार भारत के मामले में भी ट्रम्प प्रशासन का मानना है कि भारत, अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाता है अतः अमेरिका भी भारत से आयात किए जा रहे कुछ उत्पादों पर 100 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा। इस संदर्भ में हालांकि केवल भारत का नाम नहीं लिया गया है बल्कि ह्लटिट फोर टेटह्ल एवं ह्लरेसिप्रोकलह्ल आधार पर कर लगाने की बात की जा रही है और यह समस्त देशों से अमेरिका में हो रहे आयात पर लागू किया जा सकता है एवं इसके लागू होने की दिनांक भी 2 अप्रेल 2025 तय कर दी गई है। इस प्रकार की नित नई घोषणाओं का असर अमेरिका सहित विभिन्न देशों के पूंजी (शेयर) बाजार पर स्पष्टतः दिखाई दे रहा है एवं शेयर बाजारों में डर का माहौल बन गया है।

अमेरिका द्वारा चीन, कनाडा एवं मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ के बढ़ाने के पश्चात इन देशों द्वारा भी अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर टैरिफ लगा दिए जाने के उपरांत अब विभिन्न देशों के बीच व्यापार युद्ध एक सच्चाई बनता जा रहा है। परंतु, क्या इसका असर भारत के विदेशी व्यापार पर भी पड़ने जा रहा है अथवा क्या कुछ ऐसे क्षेत्र भी ढूढे जा सकते हैं जिनमें भारत लाभप्रद स्थिति में आ सकता है। जैसे, अपैरल (सिले हुए कपड़े) एवं नान अपैरल टेक्सटायल का मेक्सिको से अमेरिका को निर्यात प्रतिवर्ष लगभग 450 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहता है और मेक्सिको का अमेरिका को निर्यात के मामले में 8वां स्थान है। अमेरिका द्वारा मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाए जाने के बाद टेक्सटायल से सम्बंधित उत्पाद अमेरिका में महंगे होने लगेंगे अतः इन उत्पादों का आयात अब अन्य देशों से किया जाएगा। मेक्सिको अमेरिका को 250 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कॉटन अपैरल का निर्यात करता है एवं 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नान कॉटन अपैरल का निर्यात करता है। कॉटन अपैरल के आयात के लिए अब अमेरिकी व्यापारी भारत की ओर देखने लगे हैं एवं इस संदर्भ में भारत के निर्यातकों के पास पूछताछ की मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। इन परिस्थितियों के बीच, टेक्स्टायल उद्योग के साथ ही, फार्मा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, इंजीयरिंग क्षेत्र एवं श्रम आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी भारत को लाभ हो सकता है।

यदि अमेरिका अपने देश में हो रहे उत्पादों के आयात पर टैरिफ में लगातार वृद्धि करता है तो यह उत्पाद अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे और इससे अमेरिकी नागरिकों पर मुद्रा स्फीति का दबाव बढ़ेगा। क्या अमेरिकी नागरिक इस व्यवस्था को लम्बे समय तक सहन कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर फार्मा क्षेत्र में भारत से जेनेरिक्स दवाईयों का निर्यात भारी मात्रा में होता है। यदि अमेरिका भारत के उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो इससे अधिक नुक्सान तो अमेरिकी नागरिकों को ही होने जा रहा है। भारत से आयात की जा रही सस्ती दवाएं अमेरिका में बहुत महंगी हो जाएंगी। इससे अंततः अमेरिकी नागरिकों के बीच असंतोष फैल सकता है। अतः अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन के लिए टैरिफ को लम्बे समय तक बढ़ाते जाने की अपनी सीमाएं हैं।

अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र एवं सबसे बड़ा विकसित देश है और इस नाते अन्य देशों के प्रति अमेरिका की जवाबदारी भी है। टैरिफ बढ़ाए जाने के सम्बंध में इक तरफा कार्यवाही अमेरिका की अन्य देशों के साथ सौदेबाजी की क्षमता तो बढ़ा सकती है परंतु यह कूटनीति लम्बे समय तक काम नहीं आ सकती है। अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों में भी असंतोष फैलेगा। कोई भी व्यापारी नहीं चाहता कि नीतियों में अस्थिरता बनी रहे। इसका सीधा सीधा असर विश्व के समस्त स्टॉक मार्केट पर विपरीत रूप से पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यदि यह स्टॉक मार्केट के अतिरिक्त अन्य बाजारों एवं नागरिकों के बीच में भी फैला तो मंदी की सम्भावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता है। अमेरिका के साथ साथ अन्य कई देश भी मंदी की चपेट में आए बिना नहीं रह पाएंगे। अर्थात, इस प्रकार की नीतियों से विश्व के कई देश विपरीत रूप में प्रभावित होंगे।

अमेरिका को भी टैरिफ के संदर्भ में इस बात पर एक बार पुनः विचार करना होगा कि विकसित देशों पर तो टैरिफ लगाया जा सकता है क्योंकि अमेरिका एवं इन विकसित देशों में परिस्थितियां लगभग समान है। परंतु विकासशील देशों जैसे भारत आदि में भिन्न परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक परेशानियों का सामना करते हुए विनिर्माण क्षेत्र में कार्य हो रहा है, अतः विकसित देशों एवं विकासशील देशों को एक ही तराजू में कैसे तौला जा सकता है।

भाजपा की निगाह पश्चिम बंगाल की सत्ता पर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले बिहार चुनाव के करीब 6 महीने बाद अगले वर्ष अप्रैल-मई में होने हैं। यहां सत्ता के दोनों दावेदार अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। सियासी गर्मी बढ़ गई है। दोनों दलों में बैठकों का दौर लगातार तेज हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बढ़-चढ़कर दावे भी किए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भारी बहुमत के साथ लगातार चौथी बार सरकार के गठन का दावा किया, वहीं भाजपा दिल्ली तो हमारी है... अब बंगाल की बारी है। जैसे नारे उछाल रही है। केंद्रीय बजट से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधने लगी हैं। उन्होंने बजट को चुनावी करार देते हुए कहा था कि भाजपा हर बार चुनाव से पहले वादे तो करती है, पर पूरा नहीं करती। दूसरी ओर भाजपा नेता भी राज्य सरकार पर हमले करने में जुटे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पर बहस के दौरान अपने जवाब में तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में डूबे रहने और इसे संस्थागत रूप देने का आरोप लगाया था।

वाकई अगले वर्ष होने वाला चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक और साख का सवाल है। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी रही है। पार्टी के कई पूर्व मंत्री और विधायक फिलहाल विभिन्न घोटालों के आरोपों में जेल में हैं। उसके अलावा बीते साल के शिक्षक भर्ती घोटाले ने भी सरकार और उसकी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा बीते विधानसभा चुनाव में तमाम संसाधन झोंकने के बावजूद एक तिहाई सीटें भी जीतने में नाकाम रही थी। बीते लोकसभा चुनाव में भी उसकी सीटें 18 से घटकर 6 यानी एक तिहाई रह गई थी। पर दिल्ली की जीत के बाद पार्टी बंगाल में भी उत्साहित है। यह एक खुला सत्य है कि बंगाल में भाजपा कई गढ़ों में बेटी है। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चुनाव में जीतने के बाद केंद्र में मंत्री हैं। 'एक व्यक्ति एक पद' के फार्मूले पर चलने वाली पार्टी अभी तक सुकांत की जगह कोई नया चेहरा नहीं तलाश सकी है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य में ओडिशा में तो भाजपा की सरकार बन गई है। बिहार में भी भाजपा गठबंधन के सहयोग से सरकार में है। अब स्वाभाविक ही पश्चिम बंगाल भाजपा का एक लक्ष्य है।

इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में अपने पैरों तले की जमीन लगातार मजबूत करने में लगी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद उसके मंत्रियों की तादाद भी जद(यू) के मुकाबले ज्यादा हो गई है। यहां उसकी राह कुछ आसान नहीं नजर आ रही है। पर वास्तव में भाजपा की निगाह पड़ोस के उस पश्चिम बंगाल की सत्ता पर है। यह राज्य लंबे समय से उसके लिए कड़ी चुनौती बना हुआ है। उसने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां तक कांग्रेस और सीपीएम का सवाल है, हाथ मिलाकर लड़ने के बाद भी (बावजूद भी) दोनों पार्टियां अब तक चुनावी लड़ाई को तिकोना बनाने में विफल रही हैं। नाकाम रही हैं। विधानसभा में तो ज्यादातर सीटों पर इनके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा सके थे अब सीपीएम ने अपने पैरो तले से लगातार खिसकती जमीन पर अंकुश लगाकर नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए हाल के राज्य सम्मेलन में कई फेरबदल किए हैं। पार्टी की परेशानी यह है कि नए और युवा चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं परन्तु उसका दावा है कि अगले चुनाव में खासी टक्कर देगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी धीरे-धीरे सीपीएम जैसी स्थिति में पहुंच गई है। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पिछला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था। उन्होंने इस बार भी साफ कर दिया है कि पार्टी अगला विधान सभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद वह आप की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा चुकी है। क्या भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी?

दक्षिण में हिंदी विरोध : नई शिक्षानीति त्रिभाषा फार्मूले पर जोर देती

स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि किस तरह हिंदी सोखने को लेकर लोगों में बहुत सीमित आकर्षण है। उधर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि हिंदी थोपने का उसका कोई इरादा नहीं है तो तमिलनाडु ने भी स्पष्ट कर दिया कि वह हिंदी सीखने का नहीं बल्कि इसे थोपे जाने का विरोध कर रहा है। जाहिर है दोनों एक दूसरे के उलट बोल रहे हैं। वास्तव में, नई शिक्षा नीति हर जगह हिंदी पढ़ाने पर जोर नहीं देती है बल्कि त्रि-भाषा फामूर्ले पर जोर देती है जिसमें कहा गया है कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भारत की मूल भाषाएँ होनी चाहिए। तमिलनाडु में दो-भाषा फामूर्ले का पालन हो रहा है। और इसे वह जारी रखना चाहती है। वह 1937 से हिंदी थोपे जाने का विरोध कर रही है। हालांकि, 1967 में यह मसला शांत हो गया था। जब केंद्र ने हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति जताई। अभी तमिलनाडु के पास संदेह करने के कारण हैं क्योंकि अप्रैल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय भाषा समिति को संबोधित करते हुए कहा था कि अब समय आ गया है कि हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह ले लेनी चाहिए। हालांकि केंद्र तीन भाषा संबंधी नीति पर जोर देता है, लेकिन इसे देश में कहीं भी सही मायने में लागू नहीं किया जा सका है। उत्तर भारत में तो दक्षिण की किसी भी भाषा को सीखने पर जोर नहीं दिया गया है।

तमिलनाडु ने एक बार फिर से केंद्र के साथ भाषा युद्ध छेड़ दिया है। वह त्रिभाषा फामूर्ले को लागू करने वाली केंद्र सरकार की नीति का विरोध कर रहा है। हालिया विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान से पैदा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राज्य नई शिक्षा नीति को लागू नहीं करेंगे तो उनके शिक्षा अनुदानों के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि रोक दी जाएगी। तमिलनाडु इसे संविधान का अपमान और हिंदी थोपने का प्रयास मानता है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन द्वारा लिखे गए पत्रों के जवाब में शुरू हुआ यह वाक-युद्ध अब केंद्र व राज्य सरकार के बीच पूर्ण टकराव का रूप लेता जा रहा है। इस विवाद में अब कर्नाटक भी शामिल हो गया है। उसने तमिलनाडु का समर्थन करने का वादा किया है।

कन्नड़ विकास प्राधिकरण (कविप्रा) में तो त्रिभाषा-फामूर्ले को द्विभाषा नीति में बदलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कर्नाटक को लगता है कि केंद्र का भाषा संबंधी फरमान उसकी भाषा की अस्मिता पर सीधा हमला है। केरल व दो तेलुगु राज्य - आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में स्थिति थोड़ी अलग है। ये दोनों प्रदेश प्रदेश तमिलनाडु के साथ सहानुभूति रखते हैं और अपनी-अपनी मातृभाषा के विकास का भी समर्थन करते हैं, लेकिन हिंदी थोपे जाने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई देते हैं। उनको भरोसा है कि उनकी संस्कृति की रक्षा होगी। और मानते हैं कि अपनी अस्मिता पर होने वाले किसी भी तरह के हमले से वे बच सकते हैं। यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब स्टालिन ने 27 अगस्त को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की, क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य को केंद्रीय फंड नही मिल रहा था। उन्होंने रेखांकित किया कि- शिक्षा को अनसुलझे नीतिगत मतभेदों का बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए मगर मुद्दा तब गरम हो गया, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया कि- फंड जारी करना नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पत्र लिखकर संकीर्ण नजरिया छोड़ने की सलाह दी।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि भी मुख्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि उनकी सरकार जान बूझकर छात्रों को हिंदी सीखने से रोक रही है।

भाजपा-आरएसएस का मानना है कि - अखंड भारत की उनकी योजना को साकार करने में हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मुद्दा भाजपा और द्रमुक के बीच के वैचारिक अंतर से भी जुड़ा है क्योंकि- प्रभुता के लिए विविधता ही वह विशेषता है जो भारत को जोड़ती है जबकि भाजपा एकरूपता की बात करती है। मजेदार बात है कि -पड़ोसी राज्य केरल में इस मुद्दे का कोई असर नहीं है जबकि शिक्षा के मामले में उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल के लोग दुनिया भर को यात्राएं करते हैं और वे नई-नई भाषाएं सीखने में माहिर हैं। फिर भी मलयालम के प्रति उनका प्यार कम नहीं हुआ है। उसने तीन भाषा संबंधी फामूर्ला लागू कर रखा है। लेकिन वह भी हिंदी थोपे जाते का विरोधी है और इस मुद्दे पर तमिलनाडु के साथ है।

इसी प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने भी त्रि-भाषा नीति लागू कर रखी है, जिसकी एक वजह तो निजाम शासन है जिसमें उर्दू के साथ तेलुगू और हिन्दी पर भी जोर था। यहां लोगों को मिश्रित भाषा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री

एनटी रामा राव ने भाषा का मुद्दा या तेलुगु गौरव का मसला उठाया था लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सका। दरअसल, पिछले वर्ष चुनाव हारने वाले विभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु माध्यम के स्कूलों की जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनवाए। इसका कई लोगों ने स्वागत किया क्योंकि उन्हें रोजगार के अवसर दिखाई दिखा। कर्नाटक में भी अनेक स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं और उसने अपने आस-पास के मुंबई, कोंकण और हैदराबाद जैसे पड़ोसी क्षेत्रों की भाषाओं को अपनाया है। इससे भाषा को लेकर राज्य का नाजरिया संतुलित बना है और त्रिभाषा फामूर्ले के माध्यम से इसे अपनाने में कोई समस्या नहीं हुई है। मगर कर्नाटक अब भी यही कह रहा है कि- त्रिभाषा नीति देश में कहीं लागू नहीं है।

भारत बना रेप सिटी आफ द वर्ल्ड

विदेशी महिलाओं के प्रति यह संवेदनहीनता एवं बर्बरता कब तक चलती रहेगी? भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में विदेशी महिलाओं को लेकर गलत धारणा एवं विकृत सोच कायम है जो भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को धुंधलाती है। देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिटिश पर्यटक के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर हमें शर्मसार किया है, झकझोर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि नारी अस्मिता को कुचलने की हिंसक मानसिकता का तोड़ हम अब भी क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? क्यों नये-नये एवं सख्त कानून बन जाने के बावजूद नारी की अस्मिता एवं अस्तित्व असुरक्षित है? क्यों हमारे शहरों को रेप सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये दरिन्दगीभरी एवं त्रासद घटनाएं होती रहेंगी? नारी की अस्मत का सरेआम लूटा जाना एवं उन पर हिंसा - एक घिनौना और त्रासद कालापृष्ठ है और उसने आम भारतीय को भीतर तक झकझोर दिया।

कौन मानेगा कि यह वही दिल्ली है, जो करीब तीन दशक पहले निर्भया के साथ हुई निर्ममता पर इस कदर आन्दोलित हो गई थी कि उसे इंसाफ दिलाने सड़कों पर निकल आई थी। जाहिर है, समाज की विकृत सोच को बदलना ज्यादा जरूरी है। रेप, यौन-दुष्कर्म, व्यभिचार जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रेपिस्टों एवं दुष्कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और पुलिस व्यवस्था को और चाक-चौबंद करने की मांग के साथ समाज के मन-मिजाज को दुरुस्त करने का कठिन काम भी हाथ में लेना होगा। ये घटनाएं शिक्षित समाज के लिए बदनुमा दाग है। अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो फिर कानून का खौफ किसी को नहीं रहेगा और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। कानून कितने भी क्यों न हों जब तक समाज स्वयं महिलाओं को सम्मान नहीं देगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। समाज तमाशबीन बना रहेगा तो फिर कौन रोकेगा हैवानियत, दरिन्दगी को, बलात्कार को।

जैसे-जैसे देश आधुनिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है, नया भारत-सशक्त भारत-शिक्षित भारत बनाने की कवायद हो रही है, वैसे-वैसे महिलाओं पर हिंसा एवं यौनाचार के नये-नये तरीके और आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। अवैध व्यापार, बदला लेने की नीयत से तेजाब डालने, साइबर अपराध, आनलाइन मित्रता और लिव इन रिलेशन के नाम पर यौन शोषण एवं हिंसा के तरीके हैं। पहले कहा जाता था कि ऐसे अपराध केवल निरक्षर और दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं लेकिन आजकल शहरों और महानगरों में महिलाओं एवं विशेषतः विदेशी महिलाओं के साथ अन्याय एवं यौन-दुष्कर्म की खबरें देखने और पढ़ने को मिल जाती हैं। हम सभी कल्पना रामराज्य की करते हैं पर रच रहे हैं महाभारत। महाभारत भी ऐसा जहां न कृष्ण है, न युधिष्ठिर और न अर्जुन। न भीष्म पितामह हैं, न कर्ण। सब धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनि बने हुए हैं। न गीता सुनाने वाला है, न सुनने वाला। बस हर कोई द्रोपदी का चीरहरण कर रहा है। सारा देश चारित्रिक संकट में है। जब समाज की मानसिकता दुराग्रहित है तो दुष्कर्म एवं दुष्प्रवृत्तियां ही होती हैं। कोई आदर्श संदेश राष्ट्र को नहीं दिया जा सकता। जब कभी ऐसी किसी खौफनाक, त्रासद एवं डरावनी घटना की अनेक दावों के बावजूद पुनरावृत्ति होती है तो यह हमारी जबावदारी पर अनेक सवाल खड़े कर देती है।

बड़ा सवाल यह है कि नारी अस्मिता को कुचलने की हिंसक मानसिकता का तोड़ हम अब भी क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? क्यों नये-नये एवं सख्त कानून बन जाने के बावजूद नारी की अस्मिता एवं अस्तित्व असुरक्षित है? क्यों हमारे शहरों को रेप सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ये दरिन्दगीभरी एवं त्रासद घटनाएं होती रहेंगी? नारी की अस्मत का सरेआम लूटा जाना एवं उन पर हिंसा - एक घिनौना और त्रासद कालापृष्ठ है और उसने आम भारतीय को भीतर तक झकझोर दिया।

प्रश्न है कि आखिर हम कब औरत की अस्मत को लुटने की घटना और हिंसक मानसिकता पर नियंत्रण कर पायेंगे? कब हम विदेशी लोगों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक आतिथ्य प्रदान करने की पात्रता विकसित कर पायेंगे? अफसोसजनक यह है कि नये-नये नारों एवं उद्घोषों के साथ दुनियाभर के लोगों को भारत आने का आग्रह किया जाता है, मगर विदेश से भारत घूमने आने वाली महिलाओं के साथ ऐसी खौफनाक एवं डरावनी घटनाएं होना न केवल चिन्ताजनक बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा सवाल है कि विदेशों में भारत की छवि पर दाग न लगे, इसके लिये सरकार को सख्त होना होगा। भारत में जिस ह्यअतिथि देवो भवह्ल एवं ह्यवसुधैव कुटुम्बकमह्ल का हवाला दिया जाता रहा है, उसे सचमुच जमीन पर उतारना या सुनिश्चित करना सरकार एवं प्रशासन का ही दायित्व है। एक आदर्श-शासन-व्यवस्था, सृस्-ंस्कृत एवं सभ्य देश एवं समाज के लिये ऐसी घटनाओं का बार-बार होना भी शर्मनाक ही कहा जायेगा। हर व्यक्ति एक न्यूनतम आचार संहिता से आबद्ध हो, अनुशासनबद्ध हो। जो व्यवस्था अनुशासन आधारित संहिता से नहीं बंधती, वह विघटन की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है।

अतिथि देवो भवः भारतीय संस्कार में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आए दिन विदेशी मेहमानों के साथ हो रहे अपराध, यौन-दुराचार एवं व्यभिचार इसे धता बता रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद विदेशियों के साथ होने वाले अपराध कम नहीं हो रहे, ऐसी ही दो विदेशी महिलाओं संग हुई दरिंदगी की घटनाओं को सुन भारतीय लोगों का दिल दहल गया। कर्नाटक के हंपी में इस्राइली पर्यटक समेत दो महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दिल्ली में एक ब्रिटिश पर्यटक से दुराचार का घृणित मामला सामने आया है। थोड़े-थोडे.अन्तराल के बाद होने वाली ऐसी घटनाएं न केवल शर्मसार कर रही है बल्कि भारत के संस्कारों एवं अस्मिता पर भी दाग लगा रही है। हाल के दिनों में भारत में यौन अपराधों की बाढ़-सी आई हुई है। न केवल विदेशी बल्कि भारतीय महिलाओं के साथ घृणित यौन अपराधों की इन तमाम घटनाओं को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस नैतिक पराभव का कारण क्या है? कहीं न कहीं ये जीवन मूल्यों में क्षरण एवं विकृत होती मानसिकता का भी परिचायक है। दरअसल, इंटरनेट और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की बाढ़-सी आई हुई है। देश का युवा उसकी चपेट में आकर भटकाव की राह में बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करना सरकार एवं प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए एवं सामाजिक जागृति का माहौल भी बनाया जाना चाहिए।

निश्चय ही विदेशी महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे घिनौने एवं दुराचारी कृत्य देश की छवि को धूमिल करने वाले है। हंपी की घटना तो भयावह थी, जिसमें रात में कैंपिंग कर रहे तीन पर्यटकों को नहर में फेंक दिया गया और तीन अपराधियों ने इस्राइली महिला व एक भारतीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नदी में फेंके गए एक पर्यटक की मौत हो गई, जिसका शव बरामद कर लिया गया। पर्यटकों में एक अमेरिकी व दो भारतीय थे। बदमाशों ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि मारपीट व लूटपाट भी की। हालांकि, तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा को जो आंच आई है, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। इसने न सिर्फ समाज की छवि को धूमिल किया, बल्कि देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव डाला है। यह भारतीय पर्यटन को आहत कर सकता है, बहुत संभव है कि विदेशी सरकारें भारत आने वाले पर्यटकों को लेकर कोई नकारात्मक एडवाइजरी जारी करें।

समाज विज्ञानियों को आत्ममंथन करना होगा कि यौन अपराधों को लेकर सख्त कानून बनने के बावजूद इस आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? विदेशों में भारत की छवि यौन अपराधियों के चलते लगातार क्षत-विक्षत हो रही है। गाहे-बगाहे सुनसान पर्यटक स्थलों पर यौन दुर्व्यवहार की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। लेकिन दिल्ली के एक होटल में एक ब्रिटिश पर्यटक के साथ दुष्कर्म का मामला अधिक चिन्ताजनक है। एक युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करके भारत घूमने आई ब्रिटिश महिला को दिल्ली बुलाया और एक होटल में दुष्कर्म किया। इस मामले में ब्रिटिश दूतावास ने संज्ञान लिया है। सवाल है कि जब ऐसी कोई आपराधिक घटना हो जाती है और जनाक्रोश उभरता तथा मामला तूल पकड़ लेता है, तभी सरकार, प्रशासन एवं पुलिस की नींद क्यों खुलती है? यही सक्रियता अगर सामान्य स्थितियों में भी कायम रहे, तो शायद आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के भीतर कानूनी कार्रवाई का डर बन सकता है और इस तरह ऐसे अपराधों को पहले ही रोका जा सकता है।

घूँघट की बगावत

23 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

पर्यावरण को स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य

आप मानें या न मानें, लेकिन भारत में इससे जुड़े रवैये की जड़ें कहीं न कहीं हमारी जाति व्यवस्था से जुड़ी हैं। अच्छी बात है कि स्वतंत्रता के बाद जाति से जुड़े अस्पृश्यता के पहलू को आपराधिक कानून बना दिया गया, लेकिन व्यवहार में वह रवैया किसी न किसी रूप में कायम रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस स्थापित धारणा को अपने क्रियाकलापों से चुनौती देने की दिशा में कदम बढ़ाए, जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण से भी यह परिवर्तन आवश्यक है।

देश वास्तव में तभी स्वच्छ हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना उसका भी दायित्व है, जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय की बंधी हुई जिम्मेदारी नहीं। यह दारोमदार केवल घरों को साफ रखने तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें व्यापक पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निहित होगी। ऐसी अनुभूति आरंभ से ही जगाई जा सकती है जिसके लिए स्कूलों से शुरूआत करना श्रेयस्कर होगा।

गत दिवस राज्यसभा में यह जानकारी दी गई कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दशकों पुराने करीब 2,424 कूड़ा स्थलों में से 701 का कूड़ा हटाया जा चुका है, जबकि 1,179 कूड़े के टीलों को समतल करने का काम अभी प्रगति पर है। इससे यह पता चलता है कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए अभी कितना काम किया जाना बाकी है। स्वच्छता को कोई प्रक्रिया या परिणाम न कहकर संस्कार की संज्ञा देना उचित होगा। इसका ज्ञान मुझे अपने श्वसुर जी से मिला था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि गंदा करना हमारा अधिकार है और साफ करना किसी और की जिम्मेदारी, जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक हमारा देश-समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। स्वच्छता के संस्कार से मेरा अगला साक्षात्कार मेरी विदेश में नियुक्ति के दौरान हुआ, जहां मैंने पाया कि सार्वजनिक स्थलों और यहां तक कि धनी एवं शक्तिशाली लोगों के यहां साफ-सफाई का जिम्मा किसी एक विशेष सामाजिक वर्ग का नहीं था। कई देशों में तो स्कूल और अभिभावक ही बच्चों को यह शिक्षा देते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना उनकी जिम्मेदारी है।

मलेशिया में 1990 से 1993 के बीच नियुक्ति के दौरान मैं भारतीय मूल के एक वकील के संपर्क में आया। वह कुष्ठ निवारण अभियान के साथ भी तन्मयता से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे एक रोचक वाकया सुनाया। वकालत से पूर्व वह मलेशिया के एक प्रतिष्ठित स्कूल में अध्यापक थे। उस स्कूल में कुलीन परिवारों, जिनमें शाही परिवारों के बच्चे भी शामिल थे, पढ़ते थे। स्कूल में एक व्यवस्था बनी हुई थी कि छात्रों का समूह शौचालयों की भी सफाई करेगा। शिक्षकों का समूह इस गतिविधि की निगरानी करता था, जो खुद बारी-बारी से साफ-सफाई का काम करते थे। ऐसी ही एक स्वच्छता गतिविधि के दौरान उन्होंने देखा कि शाही परिवार से जुड़ा एक बच्चा शौचालय की सफाई नहीं कर रहा था, जबकि उसके समूह के अन्य छात्र स्वच्छता कार्य में जुटे थे। पड़ताल करने पर पता चला कि वह दूसरे छात्रों को पैसे देकर अपने हिस्से की सफाई से बच निकलता था। मेरे मित्र ने उस छात्र को तलब किया।

उन्होंने छात्रों को निर्देश दिया कि इस बार समूह का कोई अन्य छात्र सफाई नहीं करेगा और पूरे शौचालय उसी को साफ करने पड़ेंगे, जो अब तक इससे बचता आया था। चूंकि उस बच्चे के पिता एक देश के सुल्तान थे, जिनकी अनुशासनप्रियता प्रसिद्ध थी, इसलिए स्वाभाविक था कि उसने यह सुनिश्चित करना ही बेहतर समझा कि यह किस्सा उसके पिता तक न पहुंचे।

इस प्रकार उसने सफाई के निर्देश का पालन किया। इससे मुझे यही सीख मिली कि विश्व के प्रतिष्ठित स्कूलों में संपन्न लोगों के बच्चों से भी शौचालय साफ कराए जाते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि कोई भी काम गंदा या निचले स्तर का नहीं होता। यह भारतीय समाज से बहुत अलग रवैया था।

जापानी स्कूलों में बच्चे अपने क्लास रूम, स्कूल और यहां तक कि शौचालय भी साफ करते हैं। सिंगापुर में स्कूलों की साफ-सफाई छात्रों के जिम्मे है। जहां यह काम पेशेवर स्वच्छताकर्मी करते हों, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे किसी विशेष सामाजिक वर्ग से ही न हों। भारत में भी समय आ गया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में स्वच्छता की कमान छात्र ही संभालें। भारतीय समाज के स्वरूप को देखते हुए शौचालयों की सफाई को भी स्कूली काम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

एक निश्चित आयु वर्ग के बाद बच्चों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस आयु सीमा का निर्धारण विशेषज्ञ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी पहल भारत में सदियों से कायम सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करेगी। इस बीच यह भी ध्यान रहे कि बच्चों को ऐसे स्वच्छता कार्य में लगाने से पहले उन्हें रबर बूट्स, ग्लव्स, मास्क और हेड कवर जैसे पर्याप्त सामान भी उपलब्ध कराने होंगे ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई क्षति न पहुंचे।

अपनी विराट लोकप्रियता के जरिये प्रधानमंत्री मोदी ऐसे किसी भी अभियान को गति देकर उसे सफल बना सकते हैं। गांव-गांव में घर-घर शौचालय का निर्माण स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण एवं जनकल्याण को लेकर उनकी जिजीविषा का प्रतीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्हें स्कूलों में बच्चों द्वारा शौचालय साफ करने के मुद्दे पर भी कोई सहमति बनाने के प्रयास करने चाहिए। इसे लेकर संदेह है कि गांधीजी और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर स्वच्छता की जिस मुहिम को लेकर स्वयं सक्रिय एवं समर्पित रहे, उसका कोई राजनीतिक दल विरोध करने का जोखिम उठाएगा। हालांकि कुछ सामाजिक नेता और समूह जरूर इसके विरोध में आगे आएंगे, जिसकी जड़ में समाज का सदियों पुराना सोच होगा। इस धारणा का अंत करना ही होगा कि शौचालय या सार्वजनिक स्थल पर साफ-सफाई करने से किसी व्यक्ति का सामाजिक रुतबा समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठताबोध और हीनता की भावना से जुड़े इस रवैये को बदलना ही होगा। मोदी के अतिरिक्त किसी अन्य नेता में वह क्षमता नहीं, जो इस परिवर्तन के अग्रदूत बन सकें। यदि वह ऐसा करने में सक्षम रहेंगे तो इतिहास में उनका अमिट स्थान बन जाएगा।

एक अफवाह और माहौल का बिगड़ना

नागपुर में हिंसा इसलिए भड़की, क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे लोगों ने उसकी प्रतीकात्मक कब्र वाली फोटो को जलाया। इसे लेकर ही यह अफवाह फैला दी गई कि उसमें मजहबी नारे लिखे थे। यह नितांत झूठी और शरारत भरी अफवाह थी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि इसे जानबूझकर फैलाया गया और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। यह भी लगता है कि इस अफवाह के सहारे उपद्रव करने की तैयारी की गई थी। यदि ऐसा नहीं होता दो घंटे तक आगजनी और तोड़फोड़ नहीं होती रहती। इस उपद्रव में अनेक लोग घायल हुए, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं।

यह ठीक है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसी के साथ उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई किसी भी मामले पर अपनी पसंद-नापसंद प्रकट करते समय बेलगाम न होने पाए। इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि अपने देश में कई ऐसे शासक रहे हैं, जिनका दामन दागदार है अथवा जो विवादित हैं। उनके कार्य-व्यवहार पर बहस के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे सामाजिक सद्भाव अथवा कानून एवं व्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाए।

औरंगजेब की कब्र इसी की तो निशानी है कि वहां एक ऐसा शासक दफन है, जो बेहद अत्याचारी था। तथ्य यह भी है कि औरंगजेब अकेला ऐसा मुगल शासक नहीं, जिसने अत्याचार किए हों। आखिर किन-किन मुगल शासकों या अन्य बाहरी आक्रमणकारियों की निशानियों को मिटाने की मांग की जाएगी? क्या ऐसा करने से उनसे जुड़ी कटु स्मृतियां ओझल हो जाने वाली हैं? यह समझ आता है कि औरंगजेब का महिमामंडन न होने दिया जाए और जो लोग उसकी सराहना करते रहते हैं, उनका विरोध किया जाए, लेकिन इसका भी अपना एक तरीका होना चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र एक उपेक्षित स्थल ही है। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सभी उसे हिकारत की नजर से ही देखते हैं।

नागपुर में हिंसा के बाद कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने की जो नौबत आई, उससे यही पता चलता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। जैसे औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठाकर गड़े मुर्दे उखाड़ने का अनावश्यक काम किया गया, वैसे ही उसे दयालु शासक बताकर भी माहौल बिगाड़ने में ही योगदान दिया गया। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि औरंगजेब एक क्रूर, कट्टर और मतांध शासक था, लेकिन उसकी कब्र हटाने की मांग का भी कोई औचित्य नहीं बनता। आखिर ऐसा तो है नहीं कि उसकी कब्र हट जाने से उसके काले कारनामों पर पर्दा पड़ जाएगा अथवा उन अत्याचारों का प्रतिकार हो जाएगा, जो उसने किए।

खुशियां बांटने से बढ़ती हैं

होली राजा और रंक के भेद को मिटाती है और ऊंच-नीच के भाव को हरती है, इसलिए वह सामाजिक समरसता को भी पुष्ट करती है। इससे शायद ही कोई असहमत हो कि आज हमें इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। वैसे तो हमारे प्रत्येक उत्सव सद्भाव का संदेश देते हैं, लेकिन होली यह काम कहीं अच्छे से करती है।

यह देखना-सुनना दुखद है कि सामाजिक सद्भाव का संदेश देने और हर किसी को गले लगाने को प्रेरित करने वाले इस अनूठे उत्सव पर ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि कि होली और रमजान माह में शुक्रवार की नमाज एक दिन पड़ने से कई शहरों में पुलिस-प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ रही है। यह आवश्यकता एक तरह से मनुष्यता और हमारी सामाजिकता का निरादर है। होना तो यह चाहिए कि इस अवसर पर मेल-जोल का भाव और अधिक चटख हो। आखिर भारत की पहचान इससे ही तो है कि यहां के लोग अपने सभी पर्व मिलजुलकर मनाते हैं और एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। इससे

हिचकने वाले सद्भाव के बैरी ही कहे जाएंगे। आखिर जब सदियों से ऐसा होता आ रहा है तो अब क्या समस्या है? ध्यान रहे कि समस्या तभी आती है, जब सहिष्णुता पर संकीर्णता हावी हो जाती है। संकीर्णता कट्टरता की ओर ही ले जाती है। न केवल इस संकीर्णता का परित्याग किया जाना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपसी सद्भाव का रंग और गहरा कैसे हो।

उल्लास और उमंग को खुलकर अभिव्यक्त करने वाली होली एक ऐसा उत्सव है, जो एक ओर जहां जीवन की एकरसता और जड़ता को तोड़ता है, वहीं दूसरी ओर मेल-मिलाप के भाव के साथ पारस्परिकता का भी संदेश देता है।

आज की भागम भाग की जिंदगी में इस संदेश को और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम जीवन में आनंद का महत्व समझ सकते हैं। होली के रंग उत्साह और उमंग के प्रतीक हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन यदि उल्लास न हो तो बहुत कुछ होते हुए भी जीवन रीता रह जाता है।

होली इसी उल्लास को हमारे मन-मस्तिष्क में झंकृत करती है। रंगों से सराबोर होकर हम केवल आनंद का अनुभव ही नहीं करते, बल्कि उसकी महत्ता को भी समझने में समर्थ होते हैं। रंग न हों तो जीवन नीरस हो जाता है और नीरसता को कोई एक आयोजन दूर भगाता है तो वह है रंगों का त्योहर होली। हर पर्व की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो खानपान से लेकर धार्मिक-सांस्कृतिक अनुष्ठान से जुड़ी होती हैं। होली की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है उल्लास की अनुभूति। होली उल्लास और उमंग का संचार करने के साथ यह भी बताती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं।

कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप

वर्तमान भारतीय राजनीति का सच यह है कि हर पार्टी में प्रकट या मौन हिंदुत्व समर्थक बढ़े हैं। कुछ नेताओं और पार्टियों का इस सच से सामना हुआ है कि किसी भी स्थिति में हिंदुत्व विरोधी दिखने से उनके जनाधार पर विपरीत असर पड़ेगा। उन्हें सार्वजनिक तौर पर स्वयं को हिंदुत्वनिष्ठ-धर्मनिष्ठ प्रदर्शित करना पड़ रहा है।

ऐसा करते हुए वे संघ और भाजपा को गलत हिंदुत्ववादी बताते हैं। एक समय राहुल और उनके पूर्व के रणनीतिकार भी धर्मनिष्ठ होने का प्रदर्शन कर रहे थे। वह मंदिर- मंदिर जा रहे थे। उस समय राहुल को जनेऊधारी हिंदू ब्राह्मण बताया गया था। उनकी कैलास मानसरोवर की यात्रा तक हुई।

इसके पीछे रणनीति यही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का सामना करना है तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व को भी हिंदुत्व प्रेरित राष्ट्रवाद पर आना पड़ेगा। कांग्रेस के अनेक नेता सार्वजनिक मंचों से स्वयं को हिंदू और धर्मनिष्ठ कहने लगे थे। क्या वे भाजपा, संघ या मोदी समर्थक हो गए थे? इस समय भारत सहित विश्व भर में एक अजीब किस्म के वामपंथ का प्रभाव दिख रहा है, जो राष्ट्र-राज्य से लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक मामलों और पर्यावरण, विकास, शिक्षा आदि पर अतिवादी विचार अभियान चला रहा है। सारे प्रमुख देशों में इसका असर दिख रहा है।

यह सीधे-सीधे नए तरह का फंडामेंटलिज्म है, जिसका भावानुवाद धार्मिक कट्टरता नहीं हो सकता। विदेश यात्राओं में राहुल गांधी को समय-समय पर ऐसे लोगों या समूहों के साथ देखा गया है। उनके रणनीतिकार और सलाहकारों में भी ऐसे लोग हैं। राहुल गांधी का एक आक्रामक वामपंथी नेता का स्वरूप सामने आया है।

यह स्वरूप मोदी या हिंदुत्व विचार के पुरोधाओं के विरुद्ध वैचारिक फंडामेंटलिज्म की श्रेणी में ही आएगा। इसमें वोट के लिए कट्टर मुस्लिमवाद को प्रश्रय देने का व्यवहार अपने आप शामिल हो जाता है।

हाल में राहुल गांधी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने अहमदाबाद में प्रमुख नेताओं के साथ बैठक में अपने नेताओं को दूसरी पार्टी यानी भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाने से लेकर उन्हें बारात के घोड़े तक की संज्ञा दे दी। उन्होंने भाजपा से मिलकर काम करने वाले 30-40 कांग्रेस नेताओं को निकालने की भी बात कही।

गुस्से या खीझ में वक्तव्य देने का केवल गुजरात नहीं, पूरे देश के आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर संदेश सकारात्मक नहीं गया होगा। राहुल गांधी और उनके रणनीतिकार कह सकते हैं कि कांग्रेस को जगह-जगह चुनावी जीत दिलाना और राष्ट्रीय स्तर पर भी सत्ता में लाना है तो भितरघात करने वालों तथा पार्टी के विचार और लक्ष्य के अनुरूप न काम करने वालों को बाहर करना पड़ेगा।

किसी पार्टी में अगर भितरघाती सक्रिय हों तो इसे सामान्य भाषा में गद्दारी कहते हैं। राहुल की बातों को स्वीकार कर लें तो उन्हें दूसरे दल से मिलकर काम करने वाले नेताओं को बाहर करने से रोकने वाला कोई नहीं है, किंतु यह इतना सामान्य नहीं है। उन्होंने जो कहा, उसका निहितार्थ उतना सपाट भी नहीं है। काफी समय से कांग्रेस में वैचारिक अंतर्द्वंद्व जारी है जो समय-समय उभरता रहता है। केरल में तिरुअनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ नेता शशि थरूर का मामला सामने है। चूंकि थरूर बड़े नेता हैं, इसलिए उनका मामला देशव्यापी चर्चा में आ गया। हर राज्य में ऐसे नेताओं की बड़ी संख्या है, जिन्हें इसी तरह संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जिस पार्टी के अंदर एक-दूसरे को लेकर संदेह का माहौल हो, कल्पना कर सकते हैं कि उसकी दशा क्या होगी।

थरूर ने अपने लेखन और वक्तव्य से ऐसे वैचारिक बदलाव का कोई संकेत दिया नहीं है कि वह आर-एसएस और भाजपा की विचारधारा के निकट हैं। यह अलग बात है कि सरकार की कई नीतियों खासकर मोदी सरकार की विदेश नीति पर उनके वक्तव्य व्यावहारिक तथ्यों के साथ रहे हैं। **सही को सही कहना भी किसी पार्टी में भाजपा समर्थन या आंतरिक अनुशासन तोड़ना है तो इसका कोई रास्ता नहीं है। एक समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो थरूर के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण की प्रशंसा की थी।**

गुजरात में कांग्रेस जिले-जिले से टूट कर भाजपा में समाहित होती गई। अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की दुर्दशा है। इसके कारणों को समझना होगा। कांग्रेस के अंदर नेताओं-कार्यकताओं के बीच सामंजस्य का गंभीर संकट पैदा हुआ है। असंतुष्ट खेमे जी-23 के पीछे सतह पर अनेक कारण थे, लेकिन उनमें एक प्रमुख वैचारिकी भी था। इन नेताओं को लगा कि देश की मुख्य भावना के विरुद्ध अतिवादी विचार से कांग्रेस का और बंटाधार होगा। राहुल के कई पूर्व निकटस्थ विश्वसनीय सलाहकार मुख्यधारा से बाहर हुए या नेपथ्य में चले गए। भारत की तासीर धर्म और अध्यात्म है। इसका मूल हिंदुत्व में है। हमारा राष्ट्रभाव इसी से उत्प्रेत है। सेक्युलरवाद हमारे यहां सर्वपंथ समभाव है।

सच यह है कि राहुल और उनके रणनीतिकारों के व्यवहार से पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में लोग असहज महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए जब मोदी सरकार अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने का विधेयक लाई तो कांग्रेस नेतृत्व के विपरीत कई नेताओं ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 370 हटाना बिल्कुल सही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी लगभग हर राज्य से कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व की भावनाओं के परे रुख अपनाया। महाकुंभ में आध्यात्मिक-सांस्कृतिक-पुनर्जागरण का जो विराट रूप दिखा, वह बदलते भारत का प्रमाण था, जिसे हर पार्टी के नेताओं का बड़ा वर्ग प्रत्यक्ष महसूस कर रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के इस वक्तव्य से बड़े वर्ग की असहमति थी कि क्या गंगा नहाने से गरीबी मिट जाएगी? अनेक कांग्रेसी नेता संगम में डुबकी लगाने गए। इनमें कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी थे, जिनके बारे में सूचना है कि राहुल गांधी की मंडली उनसे नाराज है। अगर राहुल और उनके रणनीतिकार वीर सावरकर जैसी हिंदुत्व विभूतियों के विरुद्ध घृणा के भाव में व्यवहार करेंगे तो उन्हें हर व्यक्ति भाजपा समर्थक ही नजर आएगा।

उत्तर भारत के राज्यों में आज भी सामंत शाही हावी

हाल ही पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट में प्रधान पति जैसी प्रथा को रोकने के लिए ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर भारी दंड की सि-फारिश की गई है। साथ ही महिलाए बेहतर तरीके से काम कर पाएं इसके लिए उन्हें एआई के जरिए बेहतर प्रशिक्षण देने और नीतिगत सुधार लाने की बात कही गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने और गांवों के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन के जरिए 1992 में तीन स्तर (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई। आगे चलकर 21 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया। 'प्रधान पति , सरपंच पति' या 'मुखिया पति' नाम के पद निर्वाचित महिलाओं के पतियों को मिलता है, जो अपनी पत्नी की जगह काम करते हैं। इस वजह से निर्वाचित महिला प्रतिनिधि बस नाममात्र की प्रतिनिधि रह जाती है और सारी शक्तियां उनके पतियों के हाथ में आ जाती हैं।

मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस समस्या का जिक्र किया है। 'पंचायती राज प्रणालियों और संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना- प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना' विषय पर जारी रिपोर्ट में इस व्यवस्था को खत्म करने की सिफारिश के साथ-साथ इसमें सुधार के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। समिति ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए 'प्रॉक्सी' यानी किसी के बदले काम करने की इस प्रथा में शामिल महिलाओं के पतियों या पुरुष रिश्तेदारों को कठोर दंड दिए जाने की बात कही है। केरल की तर्ज पर समिति ने पंचायतों और वार्ड स्तर की समितियों में लिंग के आधार पर विशेष कोटा देने के साथ-साथ प्रॉक्सी

ओटीटी प्लेटफार्म पर वेब सीरीज 'पंचायत' में ग्राम फूलेरा की प्रधान मंजू देवी (नीना गुप्ता) सब एक बड़े संकट में फंस जाती हैं, जब जिलाधिकारी को यह भनक लग जाती है कि पंचायत का असली काम तो उनके पति (रघुबीर यादव) संभाल रहे हैं । यह कहानी भारत की बहुत सी ग्राम पंचायतों की है, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिला प्रधान की जगह उनके पति या उनके घर के ही दूसरे पुरुष उनकी जगह सारा काम देखते हैं।

नेतृत्व के खिलाफ'एंटी-प्रधान पति' पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए महिला लोकपाल की नियुक्ति के सुझाव के अलावा ग्राम सभाओं के शपथ ग्रहण को सार्वजनिक समारोह की तरह आयोजित करने की बात कही है। समिति ने महिलाओं को बेहतर ट्रेनिंग देने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और एआई के जरिए उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव भी दिया है। महिला प्रतिनिधियों को पंचायत से जुड़े मुद्दे का बेहतर समाधान मिल सके इसके लिए अधिकारियों के साथ वाटसएप ग्रप बनाए जाने, पंचायत निर्णय पोर्टल के जरिए नागरिकों को प्रधानों के कामकाज और भागीदारी पर नजर रखे जाने का सुझाव दिया है।

भारत में पंचायतों में आरक्षण के स्तरों पर प्रधानपति, प्रधान प्रमुख जैसे नये स्वयंभू पदों के क्रियाकलाप जारी हैं। महिलाओं, ओबीसी और अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामलों में यह सिर्फ पतियों पर सीमित नहीं है। यह उन जातियों के नये सवर्ण और दंबगों की राजनीति के शिकार हैं यह पद जहां निर्वाचित पदों पर बैठे पुरुष और महिलाएं एक कठपुतली बनकर रह गये हैं । लेकिन यह सब कुछ ज्यादा उत्तर भारत के राज्यों में देखने को मिल रहा है जहां सामन्तशाही आज भी हावी है। पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2023 में इस मामले और इससे जुड़े दूसरे मुद्दो को जांच करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया था। मंत्रालय फिलहाल समिति की सि-फारिशों को लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। देश में पंचायत के तीन स्तरों पर लगभग 2.63 लाख पंचायतें हैं। इनमें 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.6 फीसदी (15.03 लाख) महिलाएं हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा है, जहां महिला प्रतिनिधियों की जगह पुरुष काम करते हैं। देश की पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर अधिकांश मामलों में उनके पति या उनके घर के दूसरे पुरुष कार्यभार संभालते हैं। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से गठित एक समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसे मामले ज्यादा हैं, जहां महिला प्रतिनिधियों की जगह पुरुष काम करते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com